सांध्य दैनिक

नई दृष्टिबिंदु

सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

*"सफलता किस्मत से नहीं, रोज की मेहनत से मिलती है।
छोटी-छोटी कोशिशों का सिलसिला,
एक दिन बड़ी कामयाबी बनती है...!!"*

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–170 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, गुरुवार 09 जुलाई 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और दो IAS अधिकारियों समेत 4 के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर

नई दृष्टिबिंदु / सक्ती

जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट से जुड़े भू-विस्थापितों ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत चार पक्षों के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पुर्नवास एवं पुनर्स्थापना नीति के तहत पात्र भू-विस्थापितों को भत्ता या अन्य लाभ उपलब्ध नहीं कराए गए। याचिका में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सचिव शम्मी आबिदी, सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो तथा डभरा एसडीएम को भी पक्षकार बनाया गया है।

वर्ष 2008 में हुआ था भूमि अधिग्रहण मामला सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट से जुड़ा है, जिसे पहले एथेना पावर प्लांट के नाम से जाना जाता था। जानकारी के अनुसार, प्लांट की स्थापना के लिए वर्ष 2008 में आसपास के गांवों की लगभग 1,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इस प्रक्रिया में 800 से अधिक परिवारों ने अपनी जमीन दी थी।

भू-विस्थापितों का कहना है कि पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति–2007 के तहत प्रभावित परिवारों को नौकरी अथवा नियमानुसार भत्ता दिया जाना था, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। 2013 में शुरू हुआ प्लांट, 2016 में बंद, 2022 में वेदांता ने किया अधिग्रहण याचिका के अनुसार, एथेना पावर प्लांट का संचालन वर्ष 2013 में शुरू हुआ था, लेकिन वित्तीय संकट के चलते वर्ष 2016 में इसे बंद करना पड़ा। बाद में वर्ष 2022 में वेदांता ग्रुप ने इस प्लांट का अधिग्रहण

किया और वर्ष 2025 में इसका संचालन दोबारा शुरू किया।

भू-विस्थापितों का आरोप है कि प्लांट दोबारा शुरू होने के बाद भी 400 से अधिक परिवारों को न तो रोजगार दिया गया और न ही नियमानुसार भत्ता उपलब्ध कराया गया। उनका कहना है कि वे पिछले 13 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित हैं। भू-विस्थापित परिवारों के अनुसार, वर्ष 2021 में 37 परिवारों की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। करीब दो वर्ष बाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और राज्य शासन को मामले के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति ने प्लांट प्रबंधन को पत्र जारी कर पात्र भू-विस्थापितों को नियमानुसार भत्ता देने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। कलेक्टर ने भी जारी किया था निर्देश भू-विस्थापितों का कहना है कि लगभग दो माह पहले सक्ती कलेक्टर ने भी प्लांट प्रबंधन को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पात्र परिवारों को भत्ता देने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के बाद प्रभावित परिवारों ने न्यायालय की अवमानना याचिका दायर करने का निर्णय लिया।

कलेक्टर बोले— मामले के समाधान का प्रयास जारी पूरे मामले पर सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से प्लांट प्रबंधन को पत्र जारी कर भू-विस्थापितों को नियमानुसार भत्ता भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन मामले के निराकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। फिलहाल मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होना बाकी है। याचिका में लगाए गए आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जाना है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने किया आत्मसमर्पण

3 साल से थे फरार, राजीव भवन में पैसा मंगवाने का आरोप एडह के सामने समर्पण, बेटे वैभव से भी हुई पूछताछ

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब और कोल लेवी घोटाले में फरार चल रहे कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने बुधवार को सरेंडर कर दिया। सरेंडर के साथ ही 3 साल से चल रहा उनका फरारी का दौर खत्म हो गया। रामगोपाल अग्रवाल ने रायपुर स्थित EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) के कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया।

राजीव भवन में पैसा मंगवाने का आरोप

ईओडब्ल्यू के अनुसार रामगोपाल अग्रवाल पर आरोप है कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राजीव भवन में घोटाले का पैसा मंगवाया था। शराब और कोल लेवी घोटाले में उनका नाम सामने आने के बाद से वे फरार चल रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि सरेंडर के बाद ईओडब्ल्यू ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने रामगोपाल के बेटे वैभव अग्रवाल से भी लंबी पूछताछ की है। हालांकि अभी तक अधिकारियों ने सरेंडर और पूछताछ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

शराब और कोल लेवी घोटाला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला माना जाता है। इस मामले में एडह और एऊ दोनों एजेंसियां जांच कर रही हैं। रामगोपाल अग्रवाल के सरेंडर के बाद अब जांच एजेंसियों को घोटाले के पैसों के लेन-देन और अन्य आरोपियों के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है।

न्यू लुक बायोफ्यूल्स पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन

CO_2 संयंत्र नहीं लगाने और अवैध पानी परिवहन का लगाया आरोप

"पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़, कंपनी को तत्काल बंद किया जाए"

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

जिला मुख्यालय में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने ग्राम फुलझर स्थित न्यू लुक बायोफ्यूल्स कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कंपनी पर तत्काल कार्रवाई और संयंत्र बंद करने की मांग की।

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कंपनी एथेनॉल उत्पादन के दौरान निकलने वाली जहरीली उड2 गैस को संग्रहित करने के लिए उड2 संयंत्र स्थापित नहीं कर रही है, जो पर्यावरण आयोग की अनिवार्य शर्त का उल्लंघन है।

क्या हैं आरोप : ज्ञापन सौंपने के बाद जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि उड2 संयंत्र न होने से आसपास के ग्रामीणों के साथ-साथ पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। क्षेत्र में जहरीली गैस फैलने से फेफड़े और श्वसन संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। कंपनी ने एरढ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर भी गुणवत्ताहीन लगा रखी है और चिमनियों से निकलने वाले धुएं का समुचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी रात के अंधेरे में पाइपलाइन डालकर अवैध रूप से पानी परिवहन कर रही है, जलाशय को कब्जे की नीयत से तार घेर रही है और खदानों से अवैध पानी ले रही है।

पर्यावरण मानकों का उल्लंघन : प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे ने कहा कि 12.55 एकड़ में स्थापित इस कंपनी को शर्त के अनुसार 33% में वृक्षारोपण और 15% पार्किंग स्थल बनाना अनिवार्य है, लेकिन इन नियमों को दरकिनार कर उत्पादन शुरू कर दिया गया।

कांग्रेस ने मांग की है कि विशेष टीम से पर्यावरण मानकों की जांच कराई जाए और जनस्वास्थ्य को देखते हुए कंपनी को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया जाए।

कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी : ज्ञापन के दौरान प्रदेश सचिव प्रवीण मेश्राम, महामंत्री वीरेन्द्र चंद्राकर, अशोक पंजवानी, विनय झा, प्रेम रुचंदानी, लक्ष्मण साहू, राजा तिवारी, शरद खंडेलवाल, ऋषि शास्त्री, राकेश चंद्राकर, नरेश साहू, ललित मरकाम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर भूपेश बघेल का विराम

**वडिंग ही रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष, 'यह गुड्डा-गुड्डी का खेल नहीं'
चन्नी और रंधावा से भी की बात, अनुशासन तोड़ने पर होगी कार्रवाई**

विशेष संवाददाता / चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ समय से चल रही अंदरूनी खींचतान पर नवनियुक्त प्रभारी भूपेश बघेल ने विराम लगा दिया है। चंडीगढ़ में हुई अहम बैठक के बाद बघेल ने स्पष्ट कर दिया कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे।

बैठक में आंतरिक कलह की खबरों को खारिज करते हुए बघेल ने कड़े शब्दों में कहा कि "प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी को बदलना कोई 'गुड्डा-गुड्डी का खेल' नहीं है। आलाकमान का यह फैसला आखिरी है और पार्टी अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा।"

सर्वसम्मति से स्वागत

बघेल के इस फैसले का जिला अध्यक्षों और पीसी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वागत किया है। नेताओं ने कहा कि इससे पार्टी में एकजुटता का संदेश गया है।

असंतोष दूर करने की पहल

पार्टी के भीतर उठ रहे असंतोष को शांत करने के लिए बघेल ने वरिष्ठ नेताओं चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी अलग से बातचीत की। सूत्रों के अनुसार उन्होंने आत्मीय लेकिन सख्त संदेश देते हुए कहा कि "जरूरत पड़ी तो मैं खुद आपके घर जाकर चाय पर चर्चा करूंगा, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी।"

एकजुट होकर आगे बढ़ेगी कांग्रेस

इस बड़े ऐलान के बाद साफ है कि पंजाब कांग्रेस अब गुटबाजी को किनारे रखकर एकजुट होकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। बघेल ने सभी नेताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया।

रायपुर कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई : FOREX ट्रेडिंग में 74 लाख की ठगी के 2 आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर कमिश्नरेट की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम ने FOREX ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का झांसा देकर 74 लाख रुपये की ठगी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है।

कैसे हुई ठगी : थाना न्यू राजेन्द्र नगर निवासी प्रार्थी बहादुर आर्य ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17.04.2026 को उसने गूगल पर FOREX ट्रेडिंग सर्च किया। इसके बाद उसका नंबर 'FIRSTIFY' नामक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ गया। ग्रुप के सदस्यों ने अधिक लाभ का लालच देकर उसे निवेश के लिए प्रेरित किया।

आरोपियों ने मोबाइल नंबर 9112785936 और 9657985627 से लगातार संपर्क कर प्रार्थी और उसके भतीजे से विभिन्न तिथियों में किस्तों में कुल 74,00,000 का निवेश कराया। बाद में न तो लाभ दिया गया और न ही मूल राशि वापस की गई। इस तरह फर्जी निवेश योजना के जरिए ऑनलाइन ठगी की गई।

पुलिस की जांच और गिरफ्तारी : प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 159/26, धारा 318(4) बीएनएस, 66(डी) आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। मामले को पुलिस उपायुक्त (पश्चिम क्षेत्र) संदीप पटेल और पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला ने गंभीरता से लेते हुए टीम को निर्देश दिए। तकनीकी विश्लेषण, बैंक ट्रांजेक्शन और

चेन एनालिस के आधार पर आरोपियों की लोकेशन राजस्थान में मिली।

संयुक्त टीम ने राजस्थान में कैंप कर मुकेश कुमार मीणा, 26 वर्ष, निवासी ग्राम डोला का बांस, थाना कालाडेरा, जिला जयपुर और संदीप कुमार, 24 वर्ष, निवासी शाहपुरा, थाना जाजोत, जिला सीकर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन जप्त किए गए हैं। पूछताछ में दोनों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर ठगी करना स्वीकार किया है।

जप्त मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों का तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है, ताकि गिरोह के नेटवर्क और अन्य राज्यों में की गई ठगियों का पता लगाया जा सके। प्रकरण में शामिल अन्य फरार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पूछताछ व तकनीकी जांच लगातार जारी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया, टेलीग्राम और गूगल के जरिए आने वाले निवेश संबंधी लालच में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर सेल या डायल 112 पर दें।

बसंतपुर पुलिस ने अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार, 40 पौवा देशी शराब जब्त

नई दृष्टिबिंदु/राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब, सट्टा और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना बसंतपुर पुलिस ने एक शराब कोचिया को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर आरोपी प्रणय कुंजाम, पिता नील कुंजाम, उम्र 28 वर्ष, निवासी सिंगदई को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी के पास रखी प्लास्टिक बोरी से 40 पौवा देशी शराब, कुल 7.200 बल्क लीटर, कीमती 3200 रुपये बरामद कर जप्त की गई।आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 316/2026, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायिक अभिरक्षा के बाद उसे जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया।

रायपुर नाका में जुए पर मोहन नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

12 आरोपी गिरफ्तार, 9.04 लाख नगद, 10 मोबाइल और ताश पत्ती जप्त, छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

थाना मोहन नगर पुलिस ने रायपुर नाका क्षेत्र में जुआ खेल रहे 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9,04,000 नगद, 10 मोबाइल फोन और ताश पत्ती जप्त की है। पुलिस को 8 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रायपुर नाका क्षेत्र में कुछ लोग ताश पत्ती से रुपए-पैसों का दांव लगाकर हार-जीत का जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर सभी आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया।

मामला दर्ज : इस संबंध में थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 473/2026 पंजीबद्ध कर आरोपियों के खिलाफ धारा 4, 5 छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि जुआ, सट्टा एवं अन्य अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई में थाना मोहन नगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सतर्क पुलिसिंग की सराहना की गई है।

पकड़े गए आरोपियों में

मयंक गावड़े, 30 वर्ष, सेक्टर-5, भिलाई, प्रह्लाद शर्मा, 33 वर्ष, लीलापुर वार्ड-8, चिल्फी, राजीव तिवारी, 38 वर्ष, सदर बाजार, रायपुर, हेमलाल ढीमर, 26 वर्ष, रुआबंधा, भिलाई, मनीष रात्रे, 26 वर्ष, खमरिया, बेमेतरा, पंकज कुमार काठले, 27 वर्ष, सगौनडीह, कबीरधाम, दुर्गेश कुमार बर्मन, 31 वर्ष, पंडातराई, कबीरधाम, नागेश्वर साहू, 30 वर्ष, ग्राम कांदुल, मुजगहन, रायपुर, पंकज वर्मा, 38 वर्ष, उतई, दुर्ग, हेमनंदन डहरे, 25 वर्ष, मोतीपुर, पंडरिया, कबीरधाम, संजय चोपड़ा, 52 वर्ष, सिविल लाइन, रायपुर, अमित सिंह, 43 वर्ष, हनुमान नगर, दुर्ग है। उनसे जप्त सामग्री में नगदी रकम : 9,04,000 और 10 नग मोबाइल फोन सहित ताश पत्ती शामिल है।

शांति भंग करने वाले युवक को सोमनी पुलिस ने भेजा जेल

नई दृष्टिबिंदु/राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में नशे और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सोमनी पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम नवांगांव मुढीपार में वाद-विवाद कर माहौल खराब कर रहे तुलसीराम साहू, पिता गिरधारी राम साहू, उम्र 30 वर्ष, निवासी नवांगांव मुढीपार को मौके से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक विनोद जाटव, दुलेस्वर साहू और आरक्षक कमल नेताम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सफाई कर्मियों के सम्मान और सुरक्षा का संबल बनी भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना नमस्ते

दुर्ग नगर निगम महापौर अलका बाघमार व आयुक्त सुमित अग्रवाल ने किया नमस्ते किट का नि :शुल्क वितरण

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नगर निगम दुर्ग द्वारा सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और कार्यस्थल पर उनकी सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नमस्ते योजना के तहत नमस्ते किट का वितरण प्रारंभ किया गया। महापौर अलका बाघमार एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल ने महापौर कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता दीदियों एवं सफाई कर्मियों को निःशुल्क सुरक्षा किट प्रदान कर अभियान की शुरुआत की।

नगर निगम ने बताया कि योजना के अंतर्गत निगम क्षेत्र के सभी 60 वार्डों में कार्यरत सफाई कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से नमस्ते किट उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक किट में हेलमेट, दस्ताने, मास्क, एप्रन, बरसाती सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा सामग्री शामिल है, जिससे सफाई कर्मी सुरक्षित वातावरण में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि सफाई कर्मी शहर की स्वच्छता व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे केवल सफाई का कार्य ही नहीं करते, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम सफाई कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा स्वच्छता को जनभागीदारी का आंदोलन बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम प्रशासन प्रत्येक सफाई कर्मी की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि नमस्ते किट कार्य के दौरान सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी और सफाई कर्मियों को बेहतर एवं सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने में सहायक होगी।

स्वास्थ्य विभाग प्रभारी नीलेश अग्रवाल ने कहा कि सफाई कर्मियों की मेहनत और समर्पण से ही शहर स्वच्छ एवं सुंदर बना रहता है। निगम उनके हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराता रहेगा।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग प्रभारी नीलेश अग्रवाल, लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, नरेंद्र बंजारे, लीना देवांगन, शेखर चन्द्राकर, ज्ञानेश्वर ताम्रकार, लीलाधर पाल, शशि साहू, पार्षद सुरूचि उमरे, सरिता चन्द्राकर, रंजीता पाटिल, लोकेश्वरी ठाकुर, अश्वनी निषाद, नरेश तेजवानी, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी शेखर दुबे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

खास खबर

रिसाली की दशा-दिशा बदलेगी : विकास कार्यों का विधायक ललित ने किया भूमिपूजन

नई दृष्टिबिंदु / रिसाली-भिलाई

तालपुरी, रूआबांधा के 4 वार्डों में नाली, सड़क, कम्युनिटी हॉल बनेंगे
विधायक ने कहा : पूरे 40 वार्डों में चरणबद्ध तरीके से होंगे काम

नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र में विकास को नई गति देने के लिए मंगलवार को दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और महापौर शशि सिन्हा ने 4 वार्डों में 1 करोड़ 72 लाख 8 हजार रुपये की लागत वाले कार्यों का भूमिपूजन किया। विधायक ललित ने नारियल तोड़कर तालपुरी, रूआबांधा उत्तर, रूआबांधा दक्षिण और रूआबांधा पूर्व में विकास कार्यों का शुभारंभ किया।

क्या बोले विधायक : भूमिपूजन अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं को पूरा किया जा रहा है। "डबल इंजन की सरकार रिसाली को नए कलेवर में जनता को समर्पित करेगी। रिसाली की दशा और दिशा जल्द बदलेगी।" उन्होंने कहा कि विकास के नए सोपान के तहत आज वार्ड क्र. 01 से 04 तक भूमिपूजन किया गया है। अधिकांश कार्य जनता की मांग पर आधारित हैं। विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। विधायक ने यह भी आश्वस्त किया कि जल्द ही रिसाली निगम क्षेत्र में कॉलेज और नालंदा परिसर का निर्माण भी किया जाएगा।

किन वार्डों में क्या होगा : वार्ड क्र. 01 तालपुरी – 30.22 लाख, नाली के ऊपर कव्हर, फेसिंग वर्क, डोम शेड और कव्हर ड्रेन का निर्माण। वार्ड क्र. 02 रूआबांधा उत्तर – 69.28 लाख, बाउंड्रीवाल, कम्युनिटी हॉल, पेवर ब्लॉक और रोड चौड़ीकरण। वार्ड क्र. 03 रूआबांधा दक्षिण – 42.87 लाख, सी रोड, कव्हर ड्रेन और सड़क चौड़ीकरण। वार्ड क्र. 04 रूआबांधा पूर्व – 29.71 लाख, मंच के सामने पेवर ब्लॉक, कव्हर ड्रेन सहित 5 विकास कार्य।

पूरे 40 वार्डों में होंगे काम : विधायक ललित ने कहा कि उन्होंने पूरे 40 वार्डों में भूमिपूजन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया है। वे शहर के अंतिम छोर तक पहुंचकर विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। भूमिपूजन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, महापौर परिषद सदस्य ममता यादव, पार्षद सारिका साहू, सविता ढवस, डॉ. सीमा साहू, सरिता देवांगन, धर्मेन्द्र भगत, शीला नारखेड़े, माया यादव सहित मंडल अध्यक्ष अनूपम साहू, राजू जंघेल और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

एमडी ठाकुर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष मनोनीत, क्षेत्र में हर्ष

दुर्ग। केंद्रीय गोंडवाना महासभा, धमधा गढ़ के अध्यक्ष एम.डी. (मंगल दास) ठाकुर को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। उनके मनोनयन पर सामाजिक, शैक्षणिक एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। एमडी ठाकुर लंबे समय से अनुसूचित जनजाति समाज के अधिकारों, पीड़ित एवं जरूरतमंद लोगों की सेवा तथा सामाजिक उत्थान के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। इसके साथ ही वे संगठनात्मक एवं सामाजिक गतिविधियों में भी उल्लेखनीय योगदान देते रहे हैं। उनके इसी सामाजिक समर्पण और सक्रिय कार्यशैली को देखते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

उनके मनोनयन पर ओम सत्यम शिक्षण एवं जन विकास समिति के अध्यक्ष सीताराम ठाकुर, सचिव दिलीप ठाकुर, रमेश साहू (अधिवक्ता), राहुल मरकाम तथा राजेंद्र नेताम सहित अनेक लोगों ने बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं। सभी ने विश्वास व्यक्त किया कि एम.डी. ठाकुर नई ऊर्जा, उत्साह, संवेदनशीलता और जागरूकता के साथ समाज के वंचित, शोषित एवं पीड़ित वर्गों के हितों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य करेंगे।

गनियारी पहुंचे मंत्री यादव, दिवंगत तीजन बाई के कार्यक्रम को लेकर परिवारजनों से की चर्चा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई-दुर्ग

प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव पद्म विभूषण से सम्मानित, विश्वविख्यात पंडवानी गायिका एवं छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की धरोहर दिवंगत डॉ. तीजन बाई के गृहग्राम गनियारी स्थित निवास पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवारजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं तथा इस दुःख की घड़ी में परिवारजन को संबल प्रदान किये।

शिक्षा मंत्री श्री यादव ने कहा कि डॉ. तीजन बाई का निधन केवल एक परिवार की क्षति नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपनी अद्वितीय पंडवानी शैली से छत्तीसगढ़ की लोककला को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। उनकी कला, व्यक्तित्व और सांस्कृतिक योगदान सदैव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उनके गृहग्राम गनियारी पहुंचे और 14 जुलाई को आयोजित होने वाले दशगात्र एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर परिवारजनों से चर्चा किये एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिवंगत तीजन बाई के प्रसंशक और कला जगत से आने लोगों के लिए बैठक और भोजन व्यवस्था सहित सभी कार्यक्रम गरिमापूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की उनके परिवारजनों से जानकारी लिए और उन्होंने आश्वासन दिया की शासन हर संभव सहयोग के लिए दिवंगत तीजन बाई के परिजनों के साथ है। इस अवसर पर महापौर निर्मल कोसरे, ग्राम के नागरिक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले का पहला अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम अम्बेडकर नगर में होगा शुरू, 24 घंटे मिलेगी अपने राशनकार्ड का चावल

जिले का पहला अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम सुपेला के गदा चौक स्थित अम्बेडकर नगर में शुरू होने जा रहा है। इस अत्याधुनिक व्यवस्था के माध्यम से राशनकार्डधारी अब 24 घंटे अपनी सुविधा अनुसार चावल प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम का निरीक्षण कर शुभारंभ की तैयारियों का जायजा लिया तथा सुरक्षा एवं संचालन के लिए चौकीदार और ऑपरेटर की दो शिफ्ट में ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। वन नेशन, वन राशनकार्ड योजना के तहत राशनकार्डधारी, चाहे वह जिले के किसी भी क्षेत्र में निवास करता हो या किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करता हो, अम्बेडकर नगर स्थित इस ग्रीन एटीएम से अपने हिस्से का चावल प्राप्त कर सकेगा। अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम का संचालन महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। समूह की सदस्य मशीन में चावल की आपूर्ति, संचालन एवं हितग्राहियों की सहायता के लिए उपस्थित रहेंगी। वहीं इच्छुक हितग्राही स्वयं भी मशीन का उपयोग कर चावल प्राप्त कर सकेंगे। एटीएम की क्षमता 2 .7 मीट्रिक टन है। इस व्यवस्था से लोगों को उचित मूल्य की दुकानों पर लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज एवं सुविधाजनक बनेगी।

ऐसे करेगा काम अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम : मशीन से चावल प्राप्त करने के लिए हितग्राही को सबसे पहले अपना राशनकार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठे का निशान) करना होगा। सत्यापन पूर्ण होते ही पात्रता के अनुसार निर्धारित मात्रा में चावल मशीन से स्वत : उपलब्ध हो जाएगा। केवल शासन द्वारा जारी वैध राशनकार्डधारियों को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इस दौरान खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया सहित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

घरेलू विवाद में पत्नी की गला घोंटकर हत्या का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार

पुरानी भिलाई : गमछे से गला दबाकर बेहोश किया, पीड़िता के बयान पर केस दर्ज, धारा 109 बीएनएस के तहत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने घरेलू विवाद में पत्नी की गला घोंटकर हत्या का प्रयास करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 5 जुलाई 2026 को आरोपी मिथलेश यादव, 22 वर्ष, निवासी आमा कुआ चौक, पुरैना का अपनी पत्नी से घरेलू विवाद हुआ था। विवाद के बाद पीड़िता कुछ समय के लिए मायके चली गई थी, जिसे आरोपी वापस घर ले आया। इसके बाद फिर विवाद होने पर आरोपी ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और गमछे से गला घोंटकर हत्या का प्रयास किया। हमले में पीड़िता बेहोश होकर गिर गई। परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान होश आने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी दी।

पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 351/2026, धारा 109 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी की तलाश कर 8 जुलाई 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक गमछा भी जप्त किया है।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि घरेलू विवाद या महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना या डायल 112 पर दें। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई में थाना पुरानी भिलाई के विवेचना अधिकारी और स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

24 घंटे में मिला आय प्रमाण पत्र

रायपुर। कभी सरकारी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई दिनों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब डिजिटल व्यवस्था, लोगों की मुश्किलें आसान कर रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम आयबांधा निवासी तोरण लाल के परिवार ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। उनकी बेटी निकिता के कॉलेज प्रवेश के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य था और अंतिम तिथि नजदीक आ रही थी। ऐसे में परिवार की चिंता बढ़ना स्वाभाविक था। इसी दौरान उन्हें डोंगरगांव के सेवा सेतु केंद्र की जानकारी मिली। आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचे तो 22 जून को ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया।

शराब भट्टी विरोध आंदोलन के मामले में 'आप' जिलाध्यक्ष जसप्रीत सिंह को मिली जमानत

कोर्ट ने 3 हजार के मुचलके पर किया रिहा, खुर्सीपार में 13 दिन चला था धरना, 'आप' का आरोप- सरकार बदले की भावना से कर रही कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

खुर्सीपार के शिवाजी नगर वार्ड 51 में सरकारी शराब दुकान के विरोध में हुए 13 दिवसीय आंदोलन के मामले में आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिला कायर्कारी अध्यक्ष जसप्रीत सिंह समेत अन्य आंदोलनकारियों को सोमवार को माननीय न्यायालय से राहत मिली है।।। CJ-I/JMFC दुर्ग कोर्ट ने जसप्रीत सिंह को 3,000 रुपये के नकद मुचलके पर जमानत दे दी है।

क्या है मामला

शिवाजी नगर के रहवासी इलाके में शराब भट्टी खोले जाने के विरोध में स्थानीय महिलाओं के साथ जसप्रीत सिंह 13 दिनों तक धरने पर बैठे थे। आंदोलन के दबाव में प्रशासन को अंततः शराब दुकान को वहां से हटाकर स्टेडियम के पास शिफ्ट करना पड़ा था। इस मामले में रविवार को खुर्सीपार पुलिस वारंट लेकर जसप्रीत सिंह के घर पहुंची थी। इसके बाद जसप्रीत सिंह ने सीधे अदालत में दस्तक देकर जमानत ली।

'आप' ने सरकार पर लगाए आरोप

जमानत के बाद 'आप' नेताओं ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और महिलाओं के सम्मान के लिए किया गया था। लेकिन सरकार को जनता के हितों से ज्यादा शराब बिक्री की चिंता है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ने बदले की भावना से जसप्रीत सिंह, उर्मिला, अनीता नायक, अमजद अली, सागर राम चंद्राकर, सरिता सिंह, तिलक कुमार, शंकर लाल और पिंकी शर्मा समेत निर्दोष आंदोलनकारियों पर ऱ्ह्मफ्र दर्ज कराई है। अब पुलिस भेजकर डराने की कोशिश की जा रही है।

'आप' ने कहा कि पुलिस और वारंट के डर से जनता की आवाज नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट का यह फैसला साबित करता है कि सत्य की जीत होती है। पार्टी महिलाओं के सम्मान और जनता के हक के लिए दमनकारी नीतियों के खिलाफ आगे भी संघर्ष करती रहेगी।

"विवाद को संवाद से सुलझाने के हिमायती थे चंद्रशेखर" : प्रो. डीएन शर्मा

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 19वीं पुण्यतिथि पर भिलाई में विचार गोष्ठी, लोकतंत्र व संविधान के प्रहरी विषय पर हुई चर्चा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर की 19वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को रुआबांधा एचएससीएल कालोनी स्थित परिसर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जयप्रकाश नारायण स्मारक प्रतिष्ठान और आचार्य नरेन्द्रदेव स्मृति जन अधिकार अभियान समिति के तत्वावधान में आयोजित हुआ। गोष्ठी का विषय 'लोकतंत्र एवं संविधान के प्रहरी' रखा गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में उपस्थित लोगों ने स्व. चंद्रशेखर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

समाजवादी नीतियां लागू करने की जरूरत

समिति के संस्थापक अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक आर.पी. शर्मा ने कहा कि आज स्व. चंद्रशेखर की समाजवादी नीतियों को दृढ़तापूर्वक लागू करने की जरूरत है, ताकि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रगति के अवसर मिलें।

युवा भ्रमित हो रहे हैं : प्रो. शर्मा

मुख्य अतिथि प्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉ. डीएन प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर हो रहे राजनीतिक बदलाव का युवाओं पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे जानकारी जुटाने वाले युवा भ्रमित हो रहे हैं। उन्होंने स्व. चंद्रशेखर को याद करते हुए कहा कि "वे विवाद को संवाद के माध्यम से सुलझाने के हिमायती थे और सदन से सड़क तक एक ही बात कहते थे।"

कार्यशैली का अभाव दिखता है

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एडवोकेट जमील अहमद ने कहा कि स्व. चंद्रशेखर की छवि योद्धा की थी। वे अपने कार्यकाल में जनसमस्याओं का समाधान त्वरित गति से करने में विश्वास रखते थे।

विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद देवेन्द्र यादव ने कहा कि वतर्मान में सत्ता व्यक्ति केंद्रित हो गई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के दौर में स्व. चंद्रशेखर जैसी प्रधानमंत्री की कायर्शैली का अभाव दिखता है।

सामाजिक कार्यकर्ता संतोष सिंह ने कहा कि सरकार दोषपूर्ण एजेंडे के सहारे चल रही है, जिसका दुष्प्रभाव भिलाई स्टील प्लांट और उसके कामगारों पर भी पड़ रहा है। गोष्ठी में बी.एम. सिंह और वरिष्ठ पत्रकार सहदेव देशमुख ने भी विचार रखे।

कार्यक्रम में सजपा (चंद्रशेखर) के छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव नंदकिशोर साहू, राजकुमारी, अनिता निषाद, भुवनेश्वरी, दसोदा, डी.पी. सिंह, जीवनंदन सिंह, मदन श्रीवास्तव, सत्यनारायण मुप्ता, मनराम सिंह, आर.डी. चौधरी, कपिल प्रसाद, हरिश्चन्द्र, अजय चंदेल, त्रिलोक सिंह, ए.पी. सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। अंत में जयराम पासी ने आभार व्यक्त किया।

नहीं रहे पत्रकार राजेंद्र व्यास, अरुण वोरा ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

राजनीति के पुरोधा श्रद्धेय मोतीलाल वोरा के भांजे एवं पत्रकार राजेंद्र व्यास 'ब्यासू' का 8 जुलाई को राजनांदगांव में निधन हो गया। वे मोतीलाल वोरा के प्रिय भांजे थे और परिवार से उनका गहरा आत्मीय जुड़ाव था। उनके निधन को परिवार ने अपूरणीय क्षति बताया है। बचपन से परिवार के सभी सदस्यों के साथ उनका गहरा स्नेहपूर्ण संबंध रहा और उनकी आत्मीयता सभी के हृदय में सदैव बनी रहेगी।

इस दुःखद अवसर पर उनके छोटे भाई, पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, "राजेंद्र (ब्यासू) भैया का जाना हमारे पूरे परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पिछले लंबे समय से वे बीमारी से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हर कठिन परिस्थिति का उन्होंने अद्भुत धैर्य और साहस के साथ सामना किया। हम सभी भाई-बहनों का बचपन उनके साथ बीता है। आज उनके जाने से परिवार का एक अभिन्न हिस्सा हमसे बिछड़ गया। उनकी स्नेहिल स्मृतियाँ सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेंगी। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा समस्त शोकाकुल परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"

उनकी अंतिम यात्रा आज दोपहर 3 बजे उनके निवास, हाउसिंग बोर्ड, लालबाग, राजनांदगांव से लखोली मुक्तिधाम पहुंची, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

डुमरतराई थोक बाजार से व्यापार और रोजगार दोनों को मिलेगा बढ़ावा – मुख्यमंत्री साय

डुमरतराई थोक बाजार फेस -2 का नामकरण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर : परिसर में स्थापित होगी 15 फिट ऊंची प्रतिमा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर के डुमरतराई में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा विकसित नवीन थोक बाजार फेस-2 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि परिसर का नामकरण लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर किया जाएगा तथा यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की मजबूत नींव रखी। उनके नाम पर इस आधुनिक व्यापारिक परिसर का नामकरण राष्ट्र निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार और रोजगार एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां आधुनिक व्यापारिक अधोसंरचना विकसित होती है, वहां आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है, नए निवेश आकर्षित होते हैं और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। डुमरतराई का यह आधुनिक थोक बाजार रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापार को नई गति देगा तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर लगभग 36 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस अत्याधुनिक परिसर में चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था तथा आधुनिक व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह व्यापारियों की वर्षों पुरानी आवश्यकता को पूरा करने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के साथ-साथ 'ईज ऑफ लिविंग' को भी समान महत्व दे रही है। व्यापार, उद्योग और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अनेक सुधार लागू किए गए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल अब केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की अधोसंरचना विकास परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंडल द्वारा अपनाई गई नई कार्यसंस्कृति और कुशल प्रबंधन विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई गति देंगे।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में व्यापारिक अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में डुमरतराई में आधुनिक थोक बाजार की जो परिकल्पना की गई थी, वह आज साकार हुई है। इससे व्यापारियों को आधुनिक सुविधाएं मिलने के साथ रायपुर की यातायात व्यवस्था भी अधिक सुगम होगी।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि नवीन थोक बाजार मंडल की गुणवत्ता, नवाचार और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह परियोजना प्रदेश में व्यापार, निवेश, रोजगार सृजन तथा समग्र आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। कार्यक्रम में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, व्यापारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि डुमरतराई थोक बाजार का विकास दो चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में लगभग 76 करोड़ रुपये की लागत से 536 व्यावसायिक दुकानें एवं हॉल निर्मित किए गए। द्वितीय चरण में लगभग 145 करोड़ रुपये की लागत से 154 स्वतंत्र व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया गया है। दोनों चरणों के पूर्ण होने के साथ प्रदेश को आधुनिक, सुव्यवस्थित और सवर्सुविधायुक्त थोक व्यापारिक परिसर की सौगात मिली है।

खास खबर

हिन्दी पत्रकारिता के 200 वर्ष पर विशेष पृष्ठ के लिए नवप्रदेश समूह ने प्रेस क्लब को भेंट किया ऐतिहासिक फोटो फ्रेम

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल ने किया लोकार्पण

हिन्दी पत्रकारिता के दो सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में दैनिक नवप्रदेश समाचार पत्र समूह के विशेष योगदान को सम्मानित किया गया। नवप्रदेश समूह ने कार्यक्रम के अवसर पर अपने सभी संस्करणों में लगातार दो दिन विशेष पृष्ठ प्रकाशित किए थे। प्रेस क्लब रायपुर के लोगो और कार्यक्रम के लोगो के साथ इन दोनों पृष्ठों का संयोजन कर एक ऐतिहासिक फोटो फ्रेम तैयार किया गया। मंगलवार को प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित 'मीडिया संवाद' कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल ने यह फोटो फ्रेम प्रेस क्लब को भेंट किया ।इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव गौरव शर्मा सहित समस्त पदाधिकारी, वरिष्ठ पत्रकारगण और जनसंपर्क के अपर संचालक संजीव तिवारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों ने हिन्दी पत्रकारिता की 200 वर्षों की यात्रा और मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। प्रेस क्लब पदाधिकारियों ने नवप्रदेश समूह द्वारा विशेष पृष्ठ प्रकाशन और फोटो फ्रेम भेंट करने के लिए आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री आवास 2.0 लैंड टॉक्स फोर्स की बैठक सम्पन्न, पात्र आवासहीन परिवारों को पक्का घर मिले यह सुनिश्चित हो

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास 2.0 भूमि टॉक्स फोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय प्रोजेक्ट के लिए भूमि के सर्वेक्षण एवं चिन्हांकन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को प्रधानमंत्री आवास 2.0 के लिए हितग्राही की पहचान कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने आबादी भूमि पर रहने वाले पात्र हितग्राहियों को ढूंढकर सत्यापन करना एवं उन्हें आवास उपलब्ध कराने के लिए समूचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को नगरीय निकायों में वर्तमान और भविष्य की आवासीय आवश्यकता का आंकलन कर काययीजना बनाने कहा है। जिससे समय पर हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराये जा सकें। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनांतर्गत हितग्राहियों की पहचान कर आवश्यकतानुसार आवास बनाने के लिए व्यापक काययीजना बनाने के निर्देश दिए है। बैठक में नगरीय एवं प्रशासन विकास विभाग की सचिव श्रीमती आर.शंगीता, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बस्तर पुलिस के लिए गौरव का क्षण

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बोधघाट थाना को घोषित किया छत्तीसगढ़ का "सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना"

पहली बार बस्तर क्षेत्र के किसी थाने को मिला राष्ट्रीय सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / जगदलपुर

छत्तीसगढ़ पुलिस और विशेषकर बस्तर पुलिस के लिए गौरव का अवसर है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 के लिए जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर जिले के बोधघाट थाना को छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। यह बस्तर संभाग के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार बस्तर क्षेत्र के किसी पुलिस थाने को यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है।

किन मानकों पर मिला सम्मान : गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष देशभर के थानों का मूल्यांकन कई बिंदुओं पर करता है। इसमें अपराध नियंत्रण एवं रोकथाम, अनुसंधान की गुणवत्ता, सामुदायिक पुलिसिंग, जनसहभागिता, पुलिस अधोसंरचना, नवाचार, नागरिक-अनुकूल पुलिसिंग, अभिलेख संधारण और समग्र कार्य निष्पादन जैसे महत्वपूर्ण मापदंड शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बोधघाट थाना को यह सम्मान दिया गया।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम से जारी प्रशस्ति-पत्र एवं सम्मान बस्तर के तत्कालीन आईजी पी. सुंदरराज और वर्तमान आईजी बद्रीनारायण मीना द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर बोधघाट के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौड़ और वर्तमान थाना प्रभारी निरीक्षक तामेश्वर चौहान को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक बस्तर शलभ कुमार सिन्हा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही त्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीशिमल और वर्तमान नगर पुलिस अधीक्षक सुमितकुमार धोत्रे भी मौजूद रहे।

SP शलभ सिन्हा ने दी बधाई: पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने कहा कि यह उपलब्धि बोधघाट थाना के समस्त अधिकारियों और कमर्चारियों के वर्षो के समर्पित, अनुशासित और जनोन्मुखी कार्यो का परिणाम है। उनके मार्गदर्शन में थाने ने अपराध नियंत्रण, प्रभावी कानून-व्यवस्था, सामुदायिक पुलिसिंग और नवाचार आधारित पुलिसिंग में उल्लेखनीय कार्य किए, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई।

बस्तर पुलिस ने इस सम्मान को अपने अधिकारियों-कमर्चारियों की सामूहिक मेहनत और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का प्रतीक बताया। पुलिस ने कहा कि यह सम्मान भविष्य में भी नागरिक-केंद्रित, उत्तरदायी और उत्कृष्ट पुलिस सेवा देने के लिए पूरे बल को प्रेरित करता रहेगा।

पहली ही बारिश में उखड़ी पीएम जनमन सड़क, गुणवत्ता पर उठे सवाल

कवर्धा में 2 महीने में जगह-जगह उखड़ी करोड़ों की सड़क, ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनी सड़क पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई है। दलदली से मेन रोड, खरिया होते हुए अगरी (बी) तक बनी करोड़ों रुपये की यह सड़क निर्माण के मात्र दो महीने बाद ही कई स्थानों पर उखड़ने लगी है।

क्या है स्थिति

स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क का निर्माण ग्रामीणों को लंबे समय तक सुरक्षित आवागमन की सुविधा देने के लिए किया गया था, लेकिन पहली बरसात में ही सड़क की ऊपरी परत उखड़ने लगी। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है।

ग्रामीणों का आरोप

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया गया। इसी कारण सड़क इतनी जल्दी खराब हो गई।

लोगों ने संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी से मांग की है कि: - पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए - जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए, - सड़क की गुणवत्ता के अनुरूप दोबारा मरम्मत कराई जाए

विभाग से जवाब नहीं

इस मामले में अभी तक संबंधित विभाग या निर्माण एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विभाग का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।

बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस और बिना पीओएस मशीन के उर्वरक बिक्री पर 79 बोरी उर्वरक जब्त

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

खरीफ सीजन के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जशपुर जिला प्रशासन द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, नकली उर्वरकों की बिक्री एवं अनियमित विक्रय के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विकासखंड बगीचा में बिना लाइसेंस एवं बिना पीओएस मशीन के उर्वरक विक्रय किए जाने के मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 79 बोरी उर्वरक जब्त कर उनके विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लालसाय केरकेट्टा, कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक श्रीमती क्रुसलीना मिंज तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की टीम ने विकासखंड बगीचा के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान ग्राम सुलेसा में मनोज जायसवाल द्वारा बिना वैध लाइसेंस के उर्वरक विक्रय किया जाना पाया गया। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए 35 बोरी डीएपी, 10 बोरी सुपर फॉस्फेट तथा 7 बोरी यूरिया सहित कुल 52 बोरी उर्वरक जब्त कर उनके विक्रय पर रोक लगा दी गई।

इसी प्रकार सन्ना स्थित किसान कृषि केंद्र में बिना पीओएस मशीन के उर्वरक विक्रय किए जाने का मामला सामने आने पर 27 बोरी डीएपी उर्वरक जब्त कर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों प्रकरणों की विस्तृत जांच के बाद संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने सहित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले के सभी विकासखंडों में जिला स्तरीय निगरानी दल द्वारा उर्वरक विक्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। कालाबाजारी, जमाखोरी, नकली उर्वरकों की बिक्री अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय करने वालों के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश एवं प्रचलित नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से पीओएस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक खरीदें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी तत्काल कृषि विभाग को दें, ताकि समय पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

हेरिटेज स्कूल के सामने बंद की गई नाली, स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी

दुर्ग-भिलाई निगम के पार्षदों के विवाद से बनी दिक्कत

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग बायपास रोड स्थित हेरिटेज स्कूल के सामने नाली निर्माण को लेकर दुर्ग नगर निगम और भिलाई नगर निगम के पाषर्दों के विवाद के चलते नाली को बंद कर दिया गया है। इससे बरसात के समय स्कूली बच्चों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

क्या है मामला : नेशनल हाइवे द्वारा इसी वर्ष सर्विस रोड पर नाली का निर्माण कराया गया था। बारिश शुरू होते ही पानी निकासी को लेकर दुर्ग नगर निगम और भिलाई नगर निगम के पाषर्दों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि दोनों क्षेत्रों का पानी एक-दूसरे के क्षेत्र में जा रहा है। इसी विवाद के कारण दुर्ग नगर निगम द्वारा हेरिटेज स्कूल के सामने नाली को बंद कर दिया गया।

बच्चों को हो रही दिक्कत : नाली बंद होने से बारिश का पानी सर्विस रोड पर भर जा रहा है। स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को कीचड़ और भरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अभिभावकों ने आशंका जताई है कि इससे दुर्घटना और बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि निगमों के विवाद को जल्द सुलझाकर नाली को फिर से चालू किया जाए, ताकि बच्चों को सुरक्षित आवागमन मिल सके।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

-:: ईश्तहार ::-

(रा.प्र.क्रं....../अ/6 वर्ष 2025-26)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक - जगदीप कुमार आ./ध.प. स्व. जनक राज निवासी- अहिवारा दुर्ग द्वारा ग्राम - कुरुद प.ह.नं. 46 रा.नि.मं. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 518/2 रकबा 0.007 हे. 800 वर्गफीट भूमि को रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर दिनांक 11/07/2018 के आधार पर विक्रेता श्रीमती संगीता आ. श्री जियालाल से क्रय किया गया है कि रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनांमा की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 20/07/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03/07/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय मे मामला क्रमांक : 202607101000027

विषय:- अ-6 अ
मामले की श्रेणी:- राजस्व
सन:- 2025-2026
कुरूद प.ह.न. 00046 [(हे.)]
पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार नजीर खान,
अनावेदक पक्षकार -

-:: ईश्तहार ::-

आवेदक - नजीर खान पिता/पति/विभाग- स्व.इस्माईल खान पता-केलाबाड़ी दुर्ग द्वारा कुरूद प.ह.न. 46 रा.नि.म.कोहका, तहसील व् जिला-दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न. 213 का टू. रकबा 0.021 हे.= 2228.14 वर्गफीट भूमि को विक्रेता-ध्रुव कुमार पिता स्व. रामजी एवं अन्य से क्रय किया गया था। नामांतरण पश्चात निर्मित खसरा नं.213/2 रकबा 0.021 हे.=2228.14 वर्गफीट भूमि में ऋण पुस्तिका में आवेदक का नाम दर्ज है, किन्तु वर्तमान अभिलेख में आवेदक एवं अन्य 1 का नाम प्रदर्शित हो रहा है। जिसे त्रुटी सुधार किये जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है!

अतएव इस संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 21/07/2026 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयवधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा!

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 06/07/2026 को जारी किया जाता है।

DIKESHWAR SAHU
अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

संपादकीय

ट्रस्ट की बैठक के बाद भी राजनीति तो चलती रहेगी

राम मंदिर दान चोरी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप तो मामला सामने के बाद से जारी है और इस मामले में राजनीति यूपी चुनाव तक चलने वाली है। क्योंकि भाजपा,संघ,विहिप व यूपी सरकार वही काम नहीं कर रहे हैं जो विपक्ष चाहता है, वह तो वही काम कर रहे हैं जो विपक्ष नहीं चाहता है, विपक्ष एसआईटी की जांच नहीं चाहता है, यूपी सरकार, भाजपा यही कर रही है। विपक्ष चाहता है कि ट्रस्ट के लोगों को सजा मिले और यूपी सरकार व भाजपा यही नहीं कर रही है,इससे विपक्ष को राजनीति करने का मौका मिलता रहेगा क्योंकि वह तो आरोप लगाता रहेगा कि बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटो लोगों को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ जुर्म दर्ज कर कारर्वाई की जा रही है जबकि ट्रस्ट से जुड़े बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष चाहता है कि इस मामले में संघ व विहिप के बड़े लोगों का नाम आया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको बचाया नहीं जाना चाहिए इससे विपक्ष को आरोप लगाने का मौका मिलेगा कि इनके लिए धर्म नहीं धन बड़ा हो गया है,यह भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं है यानी मौका मिलता है तो यह भी भ्रष्टाचार करते हैं।

बड़ा इंतजार किया जा रहा था राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक का। 6 जुलाई को हुई बैठक में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि लोगों को संतोष हो इस मामले में कुछ खास किया गया है। कोई बड़ा फैसला लिया गया है ।जो उम्मीद की जा रही थी वही फैसले लिए गए हैं। बैठक में तीन फैसले लिए गए हैं। एक बैठक में चंपत राय और अनिल कुमार मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। दूसरा फैसला यह किया गया है कि पूर्व आईएफएस अधिकारी कृष्णमोहन को ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बना दिया जाए, तीसरा फैसला अयोध्या में राम मंदिर के रोज के कामकाज की निगरानी के लिए सीईओ नियुक्त किया जाए। बैठक में ट्रस्ट ने माना कि दान चोरी की घटना से ट्रस्ट की छवि को नुकसान हुआ है। इसलिए भक्तों का भरोसा फिर से मजबूत करना जरूरी है। बैठक मे अच्छी बात यह है अब घोषणा की गई है कि भक्त जो भी कीमती सामान मंदिर को दान करेंगे, उसका वैरीफिकेशन किया जाएगा और भक्त जब देखना चाहेगा, उसे देख सकेगा ।उन वस्तुओं को दिखाया गया बताया जा रहा था कि जिनका पता नहीं है। समयऔर कैलेंडर

बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने यह तो नहीं बताया कि कितने दान की चोरी हुई है लेकिन यह जरूर बताया कि 31 मार्च 26 तक 582 करोड़ रुपए की चढ़ावा मिला जिसमें से 391 करोड़ रुपए ट्रस्ट के संचालन और अन्य कार्यो में खर्च किया गया है और शेष राशि बैंक में है। बैठक में यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति,संस्था या पत्रकार के पास मंदिर दान में अनियमितता का कोई ठोस प्रमाण है तो एसआईटी को दे। कोषाध्यक्ष ने माना है कि दान पेटियों से चोरी हुई है और यह गहरा दर्द,शर्मिंदगी का विषय है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए चंपत राय की सराहना की और यह भी कहा है कि वह मेरी नजर में बेदाग हैं। बताया जाता है कि एसआईटी की रिपोर्ट में जहां ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्र पर आरोप लगाए गए है, वहीं चंपतराय का उल्लेख नहीं है। इससे तो विपक्ष को आरोप लगाने का मौका मिलेगा कि एसआईटी की जांच तो अपने लोगों को बचाने के लिए कराई गई है और वही होता दिख रहा है।

अखिलेश यादव तो इस मामले में भाजपा को निशाने पर रखा है और निरंतर भाजपा पर हमला कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के कथित दान चोरी के मामले की जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेसी को सौपने के बजाय विशेष जांच दल को इसलिए सौंप दिया गया कि भाजपा के अंदर आतंरिक संघर्ष चल रहा है। यही वजह है कि अखिलेश एसआईटी की जांच का शुरू से विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो राम मंदिर ट्रस्ट भंग करने की मांग की है तथा ट्रस्ट की बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह बैठक तो दान चोरी करने वालों को बचाने के लिए बुलाई गई है। कांग्रेस का कहना है कि यदि ट्रस्ट वाकई में जांच चाहता है तो ट्रस्ट को ही भंग कर देना चाहिए। राम मंदिर दान चोरी के मामले में कांग्रेस का कहना है कि आस्था के नाम पर लोगों की भावनाओं का राजनीतिक व आर्थिक लाभ उठाया गया है ।यदि विहिप वास्तव में राम मंदिर की पवित्रता को लेकर गंभीर है तो अपने संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ कारर्वाई की मांग क्यों नहीं कर रही है।

कांग्रेस को विहिप के खिलाफ बोलने का मौका मिला है तो उसके लिए विहिप भी तो दोषी है। उसे यह बयान देने की जरूरत नहीं थी कि चंपत राय व अनिल मिश्र के ट्रस्ट से इस्तीफा देने के बाद विहिप उनके साथ मजबूती से खड़ा है। विहिप ने यह भी कहा है कि दोनों ने मामले में इस्तीफा देकर नैतिकता उच्च मानक स्थापित किया है। विहिप का यह भी कहना है कि आरोप लगा देने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। विहिप का एसआईटी व ट्रस्ट पर पूरा भरोसा है। विहिप के इस बयान से तो विपक्ष को कहने का मौका मिलता है कि विहिप व भाजपा बड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और एसआईटी बनाई इसीलिए गई है ।यूपी के सीएम योगी ने कहा है कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब दूध का दूध व पानी का पानी होता है। लोग इस बात से तो संतुष्ट नहीं हो सकते कि चोरी करने वालों को सजा मिले और चोरी न रोक पाने वाले मात्र इस्तीफा देकर बच जाएं। जनता तो चाहती है कि इस पाप में भागी बड़ा हो या छोटा हो सबको सजा मिलनी चाहिए।

राजस्व सुधारों की नई इबारत लिखता छत्तीसगढ़

ऑटो म्यूटेशन और ऑटो डायवर्सन से जमीन संबंधी सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव

विष्णु प्रसाद वर्मा, सहायक संचालक, रायपुर

सुशासन के नए डिजिटल युग में राजस्व प्रशासन अब फाइलों और लंबित प्रकरणों के पारंपरिक चक्रव्यूह से बाहर निकल चुका है। राज्य शासन के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग ने तकनीक को माध्यम बनाकर जमीन से जुड़ी सेवाओं का पूरी तरह कायाकल्प कर दिया है। 'ऑटो म्यूटेशन' (स्वत: नामांतरण) और 'ऑटो डायवर्सन' (स्वत: व्यवर्तन) जैसी जन-हितैषी व्यवस्थाओं ने विभाग को तेज, पारदर्शी और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त बनाया है। इससे आम नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर, लंबे इंतजार और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना से स्थायी मुक्ति मिली है।

पहले रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से आवेदन और भौतिक सत्यापन की थकाऊ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति से अब यह स्वत: संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही, भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) के लिए आवेदन, प्रीमियम निर्धारण और शुल्क गणना को भी आधुनिक तकनीक से त्रुटिहीन बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का यह डिजिटल गवर्नेंस मॉडल आज देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है।

आंकड़ों की जुबानी: सफलता की एक नई गाथा

राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रामाणिक आंकड़े इस ऐतिहासिक परिवर्तन की गवाही देते हैं। राज्य में अब तक कुल 1 लाख 40 हजार 607 पंजीकृत विलेखों में से रिकॉर्ड 1 लाख 40 हजार 536 मामलों का सफलतापूर्वक ऑटो म्यूटेशन किया जा चुका है। संपूर्ण प्रदेश में केवल 71 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं, जिससे विभाग ने 99.95 प्रतिशत की अभूतपूर्व सफलता दर हासिल की है।

वहीं दूसरी ओर, 'ऑटो डायवर्सन' व्यवस्था के तहत कुल 5 हजार 661 आवेदन दर्ज किए गए, जिनमें से 4 हजार 739 मामलों का त्वरित निराकरण किया गया। इस प्रकार 83.71 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण कर यह साबित कर दिया गया कि जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं को भी डिजिटल माध्यम से सुगम और पारदर्शी बनाया जा सकता है। राजस्व सेवाएँ सीधे नागरिक के जीवन, संपत्ति और निवेश से जुड़ी होती हैं; अत: इनमें गति आने से राज्य की आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिली है।

ऑटो म्यूटेशन ने बदली नामांतरण की तस्वीर

किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद भू-अभिलेखों में नाम दर्ज होना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। पुराने दौर में पटवारियों और तहसील कार्यालयों के चक्कर काटना, दस्तावेजों की जांच में महीनों गंवाना और अनिश्चितता का सामना करना आम बात थी, जिसने भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया। आज छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल चुकी है। 1 लाख 40 हजार 607 पंजीकृत विलेखों में से 1 लाख 40 हजार 536 मामलों का स्वत: नामांतरण होना यह दर्शाता है कि अब नागरिक को अपने हक के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। इस व्यवस्था से समय और धन की भारी बचत हो रही है और रिकॉर्ड रीयल-टाइम अपडेट होने से जमीनी धोखाधड़ी पर लगाम लगी है।

इस सफलता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा एक सख्त तकनीकी लॉक सिस्टम विकसित किया गया है। इसके तहत, यदि किसी संपत्ति का एक भी पुराना ऑटो म्यूटेशन लंबित है, तो संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में उस संपत्ति की अगली रजिस्ट्री तब तक नहीं हो पाएगी जब तक पिछला म्यूटेशन क्लियर न हो जाए। यह कदम निचले स्तर के प्रशासनिक अमले को जवाबदेह बनाता है।

ऑटो डायवर्सन से भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया हुई तेज

कृषि भूमि को आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग में बदलना (डायवर्सन) शहरीकरण, निवेश और रोजगार सृजन की रीढ़ है। पहले आवेदकों को शुल्क, आवश्यक दस्तावेजों और समय सीमा की स्पष्ट जानकारी नहीं होती थी। फरवरी से जून 2026 के बीच 5 हजार 661 आवेदनों में से 4 हजार 739 का त्वरित निस्तारण यह दिखाता है कि विभाग ने गाइडलाइन दरों के आधार पर प्रीमियम निर्धारण जैसी पेचीदा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर दिया है। वर्तमान में जो 922 लंबित मामले हैं, उनके पीछे अपूर्ण दस्तावेज, चालान राशि में तकनीकी अंतर या नगर तथा ग्राम निवेश के मास्टर प्लान से भिन्न प्रयोजन होना जैसे व्यावहारिक कारण हैं। इन चुनौतियों को सार्वजनिक करना विभाग की पारदशिर्ता और विश्वसनीयता को दर्शाता है।

जिला-वार प्रदर्शन ने दिखाई नई प्रशासनिक संस्कृति

ऑटो डायवर्सन के क्रियान्वयन में जिलों के बीच एक स्वस्थ और परिणाम-उन्मुख प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जो यह प्रमाणित करती है कि सुधार जमीनी स्तर पर लागू हो चुके हैं। कोरिया जिला कुल 59 प्रकरणों में से सभी 59 का शत-प्रतिशत निराकरण कर 100 प्रतिशत सफलता दर के साथ पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहा ।कोरबा जिला 98.46 प्रतिशत की सफलता दर के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

इसी तरह मुंगेली जिला 94.16 प्रतिशत मामलों का निपटारा कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बालोद जिला 93.72 प्रतिशत निस्तारण दर के साथ शीर्ष जिलों में शामिल रहा। धमतरी जिला कुल 165 प्रकरणों में से 153 का वैधानिक निराकरण कर 92.73 प्रतिशत सफलता दर के साथ राज्य में पाँचवाँ (शीर्ष-5) स्थान प्राप्त किया। धमतरी का यह प्रदर्शन नियमित समीक्षा और जवाबदेह कार्यशैली का परिणाम है।

तकनीकी सुधार और नए डिजिटल मॉड्यूल्स

विभाग अपनी वर्तमान उपलब्धियों से आगे बढ़कर एक एकीकृत 'डिजिटल इकोसिस्टम' के निर्माण में जुटा है। ?ठ्ऋ्अ्र अढक क्ला्ईी१ं३ॢ्ल इसके माध्यम से सरकारी गाइडलाइन दरें सीधे पोर्टल से प्राप्त हो रही हैं, जिससे प्रीमियम का निर्धारण मानवीय हस्तक्षेप के बिना पूरी तरह स्वचालित और पारदर्शी हो गया है।

'Diverted to Diverted' मॉड्यूल:

यदि पहले से डायवर्टेड भूमि का आंतरिक उपयोग बदलना हो (जैसे आवासीय से वाणिज्यिक), तो इस मॉड्यूल के तहत निस्तारण के लिए 15 दिवस की समय सीमा तय की गई है।

'मल्टीपल खसरा' मॉड्यूल

एक से अधिक खसरों वाली भूमि के लिए अब एक ही आवेदन में अनेक खसरों का चयन, स्वत: शुल्क गणना और ई-चालान की सुविधा मिलेगी। इसके लिए समय सीमा जुलाई 2026 रखा गया है।

'रिकवरी' मॉड्यूल

पुराने लंबित मामलों के निपटारे के लिए पूर्व भुगतानों की प्रविष्टि, शेष प्रीमियम की गणना, भू-राजस्व/उपकर की मांग और एक उच्च स्तरीय रिकवरी डैशबोर्ड की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए समय सीमा अगस्त 2026 निर्धारित किया गया है।

सुशासन का नया मॉडल बनता छग

यह ऐतिहासिक बदलाव सिर्फ तकनीकी आंकड़ों का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के पौने तीन करोड़ नागरिकों के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने का माध्यम है। किसान, गृहस्वामी, व्यापारी और औद्योगिक निवेशक सभी को अब घर बैठे अपने मोबाइल पर पारदर्शी सेवाएँ मिल रही हैं।

दिसंबर 2026 तक के लिए तय किए गए रोडमैप के अनुसार, राज्य के सभी क्षेत्रों की सैटेलाइट/ड्रोन मैपिंग, टीएनसीपी से एनओसी लिंकिंग और मुख्य भू-अभिलेख पोर्टल का वृहद् अपग्रेडेशन किया जाना है। ये कदम छत्तीसगढ़ को डिजिटल राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय बेंचमार्क के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार कर रहे हैं। तकनीक, संवेदनशीलता और जवाबदेही के इस बेजोड़ संगम से छत्तीसगढ़ ने जन-केंद्रित शासन की एक नई मिसाल पेश की है।

आधुनिक तकनीक से वन संरक्षण को नई दिशा

छत्तीसगढ़ का ऑटोमेटेड फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम बना जंगलों का सतर्क प्रहरी

धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, अशोक कुमार चंद्रवंशी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, रायपुर

(a) Fire (b) No Fire (c) Smoke (d) Smoke Fire

ऑटोमेटेड फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम एक उन्नत तकनीक है जो जंगलों में आग लगने की घटनाओं का तुरंत पता लगाकर संबंधित अधिकारियों को सूचित करती है। भारत में, भारतीय वन सर्वेक्षण और विभिन्न राज्य वन विभाग फोरेस्ट फायर अलर्ट एंड मानिटरिंग सिस्टम सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। जंगल की आग को ध्यान में रखते हुए श्फोरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम संस्करण 2.0श लाया गया है और पूरी प्रक्रिया को स्वचालित बना दिया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार वन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग कर रही है। इसी दिशा में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विकसित ऑटोमेटेड फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण सुनिश्चित कर रहा है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में विकसित यह तकनीक वन विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक तेज, प्रभावी और पारदर्शी बना रही है। इससे वन संपदा, वन्यजीवों और जैव विविधता की सुरक्षा को नई मजबूती मिली है।

अब कुछ ही मिनटों में मिलती है आग लगने की सूचना : पहले वनाग्नि की जानकारी प्राप्त करने और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में एक से दो घंटे का समय लग जाता था। इस दौरान आग कई बार बड़े क्षेत्र में फैल जाती थी। अब नई स्वचालित प्रणाली के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया केवल 5 से 10 मिनट में पूरी हो जाती है। इससे समय रहते आग पर नियंत्रण संभव हो रहा है।

उपग्रह तकनीक से होती है सटीक निगरानी : यह प्रणाली अत्याधुनिक उपग्रह तकनीक पर आधारित है। उपग्रह जंगलों में तापमान में होने वाले असामान्य बदलाव की पहचान करता है। वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद आग की पुष्टि होने पर संबंधित वन मंडल, रेंज और बीट स्तर के अधिकारियों को तत्काल एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से अलर्ट भेज दिया जाता है।

रियल टाइम मॉनिटरिंग से बढ़ी कार्यक्षमता : वन विभाग ने इस प्रणाली को जीआईएस आधारित रियल टाइम डैशबोर्ड से जोड़ा है। इसके माध्यम से अधिकारी वनाग्नि की घटनाओं पर लगातार निगरानी रखते हैं। सूचना मिलते ही फील्ड स्टाफ मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई करता है और उसकी ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करता है। इससे भविष्य की रणनीति बनाने और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने में भी सहायता मिलती है।

जनजागरूकता और पूर्व तैयारी पर विशेष जोर : वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग केवल तकनीक पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए जनभागीदारी को भी बढ़ावा दे रहा है। हर वर्ष वनाग्नि सीजन से पहले फायर लाइन निर्माण, जनजागरूकता अभियान, प्रशिक्षण तथा मॉक ड्रिल आयोजित किए जाते हैं, ताकि आग की घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके।

सरकार की प्राथमिकता है सुरक्षित वन : वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप का कहना है कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से वन संपदा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उनका मानना है कि यह प्रणाली वन संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है तथा भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी मॉडल साबित होगी।

वन संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी पहल : छत्तीसगढ़ का ऑटोमेटेड फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम आधुनिक तकनीक, त्वरित सूचना प्रणाली और प्रभावी प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया है। इससे वनाग्नि पर समय रहते नियंत्रण संभव हो रहा है और राज्य की अमूल्य वन संपदा, वन्यजीवों तथा पर्यावरण की सुरक्षा को नई मजबूती मिल रही है। यह पहल विकसित छत्तीसगढ़ और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अधिक वर्षा की स्थिति में किसान लेही पद्धति से धान की करें बुआई

मानसूनी वर्षा की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की सलाह

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र के मार्ग से सामान्यत: 14 जून के आसपास मानसून वर्षा का आगमन होता है, किन्तु इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव के कारण बस्तर में लगभग 10 दिन विलंब से मानसून आया है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्रों जैसे बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान एवं छत्तीसगढ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में मानसून पहुंच गया है। सामान्यत: जून के माह में छत्तीसगढ़ में लगभग 21 से.मी. वर्षा होती है, किन्तु इस वर्ष जून के माह में 40 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। आगामी 8 जुलाई तक पूरे राज्य में व्यापक वर्षा होने का आसार हैं। वतर्मान में बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग को छोड़कर पूरे प्रदेश में लगभग सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। विगत पांच दिनों में उपरोक्त दोनों संभागों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मानसून के देरी से आने के पश्चात् भी विगत 1 जुलाई से 6 जुलाई तक छत्तीसगढ का मैदानी भाग एवं बस्तर का पठार में अधिक वर्षा होने के कारण मानसून का अब तक का कोटा लगभग पूरा हो चुका है। अत: इस प्रकार लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए किसान बन्धुओं को सलाह दी जाती है कि खेतों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता होने पर मचाई कर नसर्री उपलब्ध होने पर रोपाई करें अथवा नसर्री की अनुपलब्धता पर लेही विधि से अंकुरित बीजों को मचाई किये हुए खेतों में ड्रम सीडर एवं छिटकवा विधि से बुवाई करें। साथ ही नसर्री एवं बीजों को कवकनाशी (कार्बेन्डाजिम) एवं जैव उर्वरकों से उपचारित कर रोपाई एवं बुवाई करें।

इस वर्ष अषाढ़ माह 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। अषाढ़ माह से प्रारंभ होकर सावन मास की हरियाली अमावस्या अर्थात हरेली तिहार तक हम खरीफ फसल की बुआई एवं रोपाई कर सकते हैं। इस बार हरेली 12 अगस्त को मनाई जाएगी। जो किसान भाई धान की सीधी बुआई करते हैं उन्हें परामर्श है कि जमीन में बतर की स्थिति में 15 जुलाई तक धान की बुआई कर लेवें। रोपाई एवं बियासी पद्धति से धान की खेती करने वाले किसान भाई 30 जुलाई तक रोपाई एवं बियासी का कार्य कर लेवें। किसी असामान्य परिस्थिति के कारण विलंब होने से यदि आप हरेली तक भी बुआई रोपाई का कार्य करते हैं तो फसल के उत्पादन में ज्यादा नुकसान नहीं होगा

चूंकि इस बार मानसून विलंब से आया है इसलिए किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि इस वर्ष धान की शीघ्र एवं मध्यम अवधि में पकने वाली प्रजातियाँ जो कि 125-130 दिन तक पक जाती है जैसे- इन्द्रावती धान, बस्तर धान-1, छत्तीसगढ़ बारानी धान, इंदिरा एरोबिक धान, एम.टी.यू. 1010, एम.टी.यू. 1153, एम.टी.यू. 1156, एम.टी.यू. 1001, विक्रम टी.सी.आर., छत्तीसगढ़ धान 1919, छत्तीसगढ़ तेजस्वी धान, महामाया आदि का उपयोग करें। एक एकड़ में सीधी बुआई एवं बियासी के लिए 30 कि.ग्रा., रोपा पद्धति में 20 कि.ग्राम तथा हाइब्रिड प्रजाति के लिए 6 कि.ग्रा. बीज का उपयोग करें। जिन खेतों में अधिक जल भराव हो गया है तथा वर्षा रुक नहीं रही हो तो लेही पद्धति से धान की बोआई करें। इस विधि में धान के अंकुरित बीजों की खेत में बुआई की जाती है

बुआई के पूर्व बीज को कार्बेन्डाजिम या किसी अन्य कवकनाशी दवा से उपचारित कर लें। 1 किलो बीज के लिए ढाई ग्राम दवा का प्रयोग करें। भूमि में नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटेशियम की पूर्ति के लिए जैव उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। धान में एजोस्पाइरिलम, पी.एस.बी., के.एस.बी. का उपयोग करना चाहिए। इन तीनों तरल जैव उर्वरकों की 2-2 मि.ली. मात्रा अर्थात 6 मि.ली. तरल पदार्थ 4 मि.ली. पानी में मिला लें। इस प्रकार तैयार 10 मि.ली. के घोल से 1 कि.ग्रा. धान बीज को उपचारित कर दें। यह उपचार पौधों को लगभग 12 कि.ग्रा. नाइट्रोजन 8 कि.ग्रा. फास्फोरस एवं 5 कि.ग्रा. पोटेशियम प्रति एकड़ प्रदान करेगा।

हरी खाद की फसलों की उत्पादन क्षमता

फसल का नाम	हरे पदार्थ की मात्रा (टन प्रति हे.)	नाइट्रोजन का प्रतिशत	प्राप्त नाइट्रोजन (किग्रा.प्रति हे.)
सनई	20-30	0.43	86-129
ढैंचा	20-25	0.42	84-105
उर्द	10-12	0.41	41-49
मूंग	8-10	0.48	38-48
ग्वार	20-25	0.34	68-85
लोबिया	15-18	0.49	74-88
कुल्थी	8-10	0.33	26-33
नील	8-10	0.78	62-78

धान की सीधी बुवाई (Direct Seeded Rice - DSR) में ब्राउन मैन्योरिंग

धान + ढैंचा (2:1) की बुवाई

वतर्मान परिपेक्ष्य में लगातार वर्षा की स्थिति में धान की लेही विधि से बुवाई- वतर्मान परिपेक्ष्य में उन क्षेत्रों में लगातार वर्षा की स्थिति निर्मित होने के कारण धान की लेही विधि से बुवाई करना उपयुक्त रहेगा। इस हेतु धान के खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होने पर खेत की रोपा पद्धति की ही तरह अच्छी तरह से मचाई कर अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर अथवा छिटकवाँ विधि से बुवाई करें। इस विधि में मध्यम अवधि में पकने वाली (120-130 दिन लगभग) उपयुक्त किस्मों (विक्रम टी.सी.आर., छत्तीसगढ़ धान 1919, छत्तीसगढ़ तेजस्वी धान, महामाया, एम.टी.यू. 1001) का चयन करें एवं इस हेतु बीज दर 40 किलों ग्राम प्रति एकड़ उपयोग करते हुए बीजों को 8-10 घंटे पानी में भिगोना चाहिए फिर इन भीगे हुए बीजों का पानी निथार दें, इसके बाद इन बीजों को पक्के फर्स पर रखकर बोरे से ठीक से ढ़क देना चाहिए। लगभग 24-30 घंटे में बीज अंकुरित हो जायेंगे। अब बोरे को हटाकर बीज को छाया में फैलाकर रखें एवं इन अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर यंत्र उपलब्ध होने पर पंक्ति में बोवाई करें अथवा छिटकवाँ विधि से बुवाई करें।

छत्तीसगढ़ में लगभग 26 लाख हेक्टेयर में धान की सीधी बुआई एवं 12 लाख हेक्टेयर में रोपाई की जाती है। सीधी बुआई में खरपतवार एक प्रमुख समस्या है एवं यदि इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल में 50 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। फसल बोने के 40 दिन बाद तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना आवश्यक है। मानव श्रम उपलब्ध होने पर बोने के 20 दिन एवं 40 दिन बाद हाथ अथवा पैडी वीडर से निंदाई करना उचित होगा। रासायनिक दवाई से भी संकरी पत्ती एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारो का प्रभावकारी निंदा नियंत्रण किया जा सकता है। इसके विकल्प निम्नानुसार है-

अंकुरण पूर्व निंदानाशक (व्यवसायिक नाम- पेन्डीमेथीलीन स्टाम्प, पेंडीगोल्ड, पेंडीलीन, धानुटांप, पेनिडा, पेंडीहबे आदि की 1000 मि.ली. मात्रा) को 150 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में बुआई के 0 से 3 दिन के बीच छिड़काव करें। पाइरेजोसल्फूरान (व्यवसायिक नाम- साथी, सेवक, पाइरोसल्फ, लाठी आदि की 80 मि.ली. मात्रा) को 150 लीटर पानी में मिलाकर बोने के 0 से 3 दिन बाद तक एक एकड़ खेत में छिड़काव करें। बिसपायरी बेक सोडियम (व्यवसायिक नाम- नोमीनी गोल्ड, एडोरा, स्ट्राइडर, बिसफोर्स आदि की 100 मि.ली. मात्रा) को 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ खेत में बोने अथवा रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद छिड़काव करें अथवा क्लोरीम्यूरान इथाइल$मेटसल्फ्यूरान मिथाइल (व्यवसायिक नाम- आलमिक्स, धारमिक्स, दिग्गज आदि की 8 मि.ली. दवा) को 150 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ खेत में बोने अथवा रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद छिड़काव करें।

बाजार में उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण रसायनों का उपयोग भी किया जा सकता है। किन्तु उपयोग के पूर्व वैज्ञानिकों अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों से परामर्श लें। खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निंदाई, मशीन से निंदाई अथवा रासायनिक दवा नियंत्रण में एक हजार से डेढ़ हजार रू. प्रति एकड़ तक खर्च आता है, किन्तु यदि समय पर खरपतवारों को नियंत्रण नहीं किया गया तो 20 हजार रू. प्रति एकड़ की हानि हो सकती है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राथमिक सहकारी सोसायटी में पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डी.ए.पी., एन.पी.के., सिंगल सुपरफास्फेट एवं पोटाश उर्वरकों का भंडारण कर दिया गया है। पिछले वर्ष के समान मात्रा में किसानों को उर्वरक देने के निर्देश जारी किए जा चुके है। रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ हरी खाद एवं नील हरित काई के उपयोग से एक एकड़ में 1 बोरी यूरिया के बराबर नाइट्रोजन प्राप्त होती है तथा मिट्टी की संरचना में भी सुधार होता है।

एक एकड़ भूमि में अधिकतम 2 बोरी यूरिया एवं 1 बोरी डी.ए.पी. का उपयोग करें। किसान भाई डी.ए.पी. की पूरी मात्रा को बुआई या रोपाई के पूर्व दे दे। 1 बोरी यूरिया को बोने या रोपाई के 30-35 दिन बाद एवं 1 बोरी यूरिया को बोने या रोपाई के 60-70 दिन बाद दिया जावे। जुलाई एवं अगस्त माह में धान की खेती में आने वाले कार्यो जैसे बुआई, रोपाई, उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन के लिए यह परामर्श जारी किए जा रहे है। सभी कृषि अनुसंधान केन्द्रों, कृषि महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों में कृषक सलाह केन्द्र स्थापित किए गए हैं। किसी भी प्रकार की कठिनाइयों के निराकरण के लिए अपने निकटस्थ कृषि अनुसंधान केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि महाविद्यालयों एवं कृषि विभाग से सम्पर्क करें।

मुद्दे की बात

डॉ.सोनाली चक्रवर्ती के साथ

यौन शिक्षा नहीं नैतिक शिक्षा की जरूरत है देश में

2 दिन पूर्व मुझसे एक 4 साल के बच्चे ने पूछा - "मैम व्हाट इज गैंग रेप"

उस समय सारे मुद्दे एक तरफ हो जाते हैं और सबसे मुख्य मुद्दा होता है क्या हम बच्चों को नैतिक शिक्षा दे पा रहे हैं? बच्चों के मन में ज्ञान विज्ञान के प्रश्न नहीं बल्कि ऐसे शब्दों का अर्थ जानने की इच्छा ही हमारे समय का पतन दिखाता है।

श्री गंगानगर राजस्थान में एक 12 साल की बच्ची ई रिक्शा लेकर अपने घर नहीं पहुंच पाती और उसे 32 बार बेचा जाता है। उस पर जो अमानुषिक अत्याचार किए जाते हैं वैसा शायद जानवर भी दूसरे जानवर के साथ नहीं करते।

क्या उन 32 लोगों में किसी के मन में कोई नैतिकता नहीं थी, कोई मानवीय संवेदनाएं नहीं थी कि उनमें से किसी एक के मन में आए कि बच्ची को सही सलामत यहां से निकाल ले! हर एक पुरुष के मन में यह पाशिवकता क्यों, कब और कैसे आ गई? स्कूलों में यौन शिक्षा अनिवार्य करने की बातें जब तक उठती ही रहती है लेकिन नैतिक मूल्यों की बातें आजकल नहीं होती।

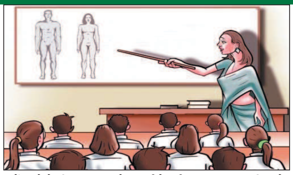

जब हम छोटे थे मॉरल साइंस (नैतिक शिक्षा) नामक एक विषय होता था जिसको पढ़कर हमें पता चलता था कि समाज में रहने के लिए एक दूसरे का ख्याल रखना जरूरी होता है। प्राचीन काल में, विशेष रूप से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में, इसे धर्म और दर्शन का अभिन्न अंग माना जाता था।

उस समय पढ़ाए जाते थे धर्म और कर्तव्य,जीवन में सही रास्ते पर चलना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, और बड़ों/शिक्षकों के प्रति सम्मान, सत्य और अहिंसा,हमेशा सच बोलना और मन, वचन, कर्म से किसी को नुकसान न पहुँचाना, चरित्र निर्माण, ईमानदारी, दया, करुणा, और विनम्रता जैसे मानवीय गुण वेदों और उपनिषदों की कहानियों के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान और जीवन जीने की कला। आज कितने घरों में बच्चों को पंचतंत्र की कहानी सुनाई जाती है?

आज स्कूलों में मॉरल साइंस नाम का विषय तकरीबन नहीं है

नैतिक विज्ञान को केंद्रीय स्तर पर (जैसे NCERT या CBSE) किसी एक अनिवार्य विषय के रूप में पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। इसके बजाय, नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत नैतिक और मानवीय मूल्यों (Values) को अन्य विषयों (जैसे भाषा और सामाजिक विज्ञान) में एकीकृत कर दिया गया है।अलग-अलग राज्यों और स्कूलों में इसे पढ़ाने का तरीका भिन्न होता है।

NCERT और CBSE की किताबों में सच्चाई, अहिंसा, और नागरिकता जैसे नैतिक मूल्यों को अन्य पाठों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। राज्य स्तर पर: छत्तीसगढ़, कर्नाटक सहित कई राज्य अपने क्षेत्रीय पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा या जीवन कौशल (Life Skills) की कक्षाओं को शामिल करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का स्पष्ट मानना है कि नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन न्यायालय इसे एक अलग अनिवार्य विषय बनाने का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि यह शिक्षा विशेषज्ञों और कार्यपालिका का कार्य है। NCERT की पाठ्यपुस्तकों में नैतिक शिक्षा को एक अलग अनिवार्य विषय के रूप में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसे अन्य विषयों (जैसे भाषा और सामाजिक विज्ञान) के माध्यम से पढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

वर्ष 2016 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'नैतिक शिक्षा' को पहली से बारहवीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बनाने की याचिका यह कहकर खारिज कर दी थी कि यह फैसला लेने का अधिकार शिक्षा बोर्ड और राज्य सरकारों के पास है। कई राज्य सरकारें अब भी अपने स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को शामिल करती हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में नैतिक शिक्षा को फिर से लागू करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए। हम सबको एक मत होकर इस फैसले पर पहुंचना चाहिए कि हमें यौन शिक्षा नहीं नैतिक शिक्षा की अधिक आवश्यकता है। यह सारी घटनाएं कड़े कानून बनने से भी अधिक मनुष्य में मनुष्यता का बोध जगाने से खत्म होंगी।

यदि आपके पास भी है इस विषय में कुछ बताने को तो हमें अवश्य बताएं।

खास खबर

भाजपा नेता अशोक चौधरी का बयान, "पीओके और बलूचिस्तान को अलग देश की मान्यता मिले, भारत में शामिल करने से नई समस्या खड़ी होगी"

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कहा - मोदी सरकार के मौजूदा रुख से सहमत हूं

भाजपा नेता और किसान नेता अशोक चौधरी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) और बलूचिस्तान के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वतर्मान में कई विद्वान, खासकर विपक्षी विचारक, यह सवाल उठा रहे हैं कि पीओके अभी तक भारत में शामिल क्यों नहीं हुआ। चौधरी ने मंगलवार को कहा, "सर्वविदित है कि पीओके में वहां की जनता पाकिस्तान सरकार के उतनी ही खिलाफत कर रही है जितनी 1971 के दौर में बांग्लादेश में हो रही थी। इसी तरह बलूचिस्तान में भी पाक सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है।"

"नंगे-भूखे समूह को शामिल कर सुख-चैन क्यों खोएं" : अशोक चौधरी ने कहा, "हमें सोचना होगा कि एक नंगे-भूखे लोगों के समूह को भारत में शामिल करके हम अपना सुख-चैन क्यों खोएं। मेरी राय है कि भारत सरकार को चाहिए कि इन दोनों प्रदेशों को पाकिस्तान के नक्शे से काटकर अलग देश के रूप में पहचान दिलवा दे। नहीं तो उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए ताकि वे पाकिस्तान की नाक में दम करते रहें। जहां तक बने हमें उनकी छद्म मदद करनी चाहिए।"

देश के अंदरूनी हालात का हवाला : पीओके को भारत में शामिल करने के विरोध में तर्क देते हुए उन्होंने कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से भारत में रह रहे मुसलमान भाइयों का अपने देश के प्रति जो समर्पण और व्यवहार देखता हूं उससे निष्कर्ष निकलता है कि पीओके को भारत में शामिल करने से कश्मीर की समस्या के साथ-साथ भारत के लिए भी नई समस्या खड़ी होगी। इसलिए इस पर सोच-विचार कर निर्णय लेना चाहिए।" अंत में अशोक चौधरी ने कहा कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार के इस मुद्दे पर निर्णय से मैं सहमत हूं।

सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए सेल मेडिक्लेम योजना 2026-27 का नवीनीकरण शुरू

भिलाई। सेल प्रबंधन ने सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके पात्र आश्रितों के लिए सेल मेडिक्लेम योजना 2026-27 के तहत नवीनीकरण और गैप केस में नवीन पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना 11 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके जीवनसाथी को द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा सुविधा मिलेगी। एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड तृतीय पक्ष प्रशासक के रूप में सेवाएं देगा। **कैसे करें नवीनीकरण :** वर्ष 2025-26 में योजना से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मी सेल मेडिक्लेम पेमेंट पोर्टल के माध्यम से, जो एसबीआई ई-पे से एकीकृत है, ऑनलाइन प्रीमियम जमा कर नवीनीकरण कर सकते हैं। जो पूर्व कर्मचारी पिछले वर्ष योजना से नहीं जुड़े थे, वे गैप केस के रूप में निर्धारित प्रीमियम चालान जमा कर आवेदन पत्र के साथ मानव संसाधन-कर्मचारी सेवा कार्यालय, पुराना स्वास्थ्य केंद्र भवन, सेक्टर-5, भिलाई में जमा कर योजना से जुड़ सकते हैं। नवीनीकरण एवं नवीन पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है। **कौन ले सकता है लाभ :** यह योजना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से सेवानिवृत्त सेल कमिर्यों, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता के कारण सेवा से पृथक हुए कर्मचारियों, सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के जीवनसाथियों, 57 वर्ष या उससे अधिक आयु में त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों तथा उनके पात्र जीवनसाथियों के लिए लागू है। योजना में पूर्व कर्मचारी एवं जीवनसाथी को अलग-अलग सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। **डिजिटल सुविधाएं :** योजना के अंतर्गत वेब एवं मोबाइल आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म से सदस्य ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान, पंजीयन, सदस्यता कार्ड डाउनलोड, नेटवर्क अस्पतालों की जानकारी, प्री-ऑथराइजेशन आवेदन, क्लेम की ऑनलाइन निगरानी और व्यक्तिगत विवरण अद्यतन कर सकेंगे। हेल्प डेस्क, टेली-कंसल्टेशन और ई-फार्मेसी की सुविधा भी पूर्ववत उपलब्ध रहेगी। अधिक जानकारी और विस्तृत सर्कुलर बीएसपी होमपेज और अग्रज संवाद वेबसाइट पर देखी जा सकती है। **महत्वपूर्ण अपील :** सेल प्रबंधन ने लाभार्थियों से अपील की है कि नवीनीकरण के दौरान पोर्टल पर दर्ज सभी जानकारियों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें। जिन सदस्यों ने पहले सेल्फ + स्पाउस (बोथ) श्रेणी में पंजीयन कराया था और अब किसी एक सदस्य

बिलासपुर में साइबर ठगी के पीड़ितों को तुरंत पैसा वापस दिलाने पर दिया विशेष प्रशिक्षण

आईजी राम गोपाल गर्ग : "असली सफलता पैसा वापस दिलाने में है, सिर्फ खाताधारक पकड़ना काफी नहीं"

एसीसीयू टीम ने 2 .36 लाख रुपये रिकवर कराए, 60 प्रकरण प्रक्रियाधीन

नई दृष्टिबिंदु / बिलासपुर

आम जनता को साइबर ठगी से त्वरित राहत दिलाने के लिए मंगलवार को पुलिस रेंज बिलासपुर में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक रेंज बिलासपुर राम गोपाल गर्ग, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह और एसपी मुंगेली भोज राम पटेल उपस्थित रहे।

रेंज के सभी साइबर थाना प्रभारियों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) के NCRP पोर्टल के दो महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग दी गई।

पैसा वापस दिलाना ही असली कामयाबी: पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने कहा कि केवल निचले स्तर के आरोपियों और बैंक खाता धारकों को पकड़ लेना पर्याप्त नहीं है। पुलिस की असली सफलता पीड़ित का ठगा हुआ पैसा उसे वापस दिलाने में है। मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के तहत अगर ठगी की रकम किसी खाते में फ्रीज हो गई है, तो कानूनी प्रक्रिया और बैंक से समन्वय कर उसे पीड़ित के खाते में कैसे वापस कराया जाए, इसकी पूरी प्रक्रिया समझाई गई।

ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल में बताया गया कि फ्रॉड के दौरान कई बार निदोष व्यापारियों या आम लोगों के खाते भी फ्रीज हो जाते हैं। ऐसे मामलों में बिना थाने के चक्कर कटवाए पोर्टल के जरिए खाते को डी-फ्रीज कैसे कराया जाए।

बिलासपुर ACCU को मिली सराहना : बिलासपुर ACCU की टीम ने मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के तहत अब तक 2,36,000 रुपये रिकवर कर पीड़ित को वापस दिलाए हैं। 60 प्रकरण वतर्मान में प्रक्रियाधीन हैं। इस उपलब्धि पर IG बिलासपुर और SSP बिलासपुर ने ACCU प्रभारी गोपाल सतपति और उनकी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की।

एसएसपी मुंगेली भोजराम पटेल ने हाल ही में मनी रेस्टोरेशन में किए गए सफल प्रयोग को केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया। प्रशिक्षण में आए अधिकारियों ने कई सवाल पूछे, जिनका समाधान कर प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई ताकि अन्य जिले भी इसे लागू कर सकें।

बैंक और संपत्ति कुर्की पर जोर : ICICI बैंक के विशेषज्ञ कमलेश वाल्दे ने बताया कि रकम वापसी के लिए बैंकों को किन कानूनी दस्तावेजों और कोर्ट आदेशों की जरूरत होती है।

अधिकारियों ने निर्देश दिए कि साइबर अपराधियों की केवल गिरफ्तारी न हो, बल्कि उनकी संपत्ति, खासकर अचल संपत्ति, की इन्वेंट्री बनाकर डायरी के साथ कोर्ट में पेश की जाए। ताकि केस चलने तक वे संपत्ति न बेच सकें और पीड़ितों को भरपाई मिल सके।

आम जनता से अपील : वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि साइबर ठगी का शिकार व्यक्ति जब थाने आए तो उसे साइबर सेल और थाने के बीच न घुमाया जाए। पुलिसिंग को जनता के लिए सुलभ बनाया जा रहा है।

अपील: साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। गंवाई गई राशि को Money Restoration Module https://mrm-ncrp.mha.gov.in/ पर जाकर वापस प्राप्त कर सकते हैं।

बीएसपी की बार एवं रॉड मिल ने बनाया नया एक दिवसीय उत्पादन रिकॉर्ड

7 जुलाई को 3,426 टन 12 मिमी टीएमटी बार का उत्पादन, पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, निदेशक प्रभारी चित्तरंजन महापात्र और टीम को बधाई

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल- भिलाई इस्पात संयंत्र की बार एवं रॉड मिल (बीआरएम) ने उत्पादन के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। बीआरएम ने 12 मिमी टीएमटी बार श्रेणी में एक दिवसीय उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विभाग ने 7 जुलाई 2026 को 3,426 टन (1,663 बिलेट्स) का उत्पादन कर इतिहास में नया रिकॉर्ड दर्ज किया। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड 8 मार्च 2026 को 3,405 टन (1,653 बिलेट्स) उत्पादन का था।

इस उपलब्धि पर भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी चित्तरंजन महापात्र और कार्यपालक निदेशक (संकार्य) राकेश कुमार ने बीआरएम की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने इसे संयंत्र की निरंतर प्रगति, टीमवर्क और उत्कृष्ट कार्य निष्पादन का प्रतीक बताया। विभागाध्यक्ष एवं मुख्य महाप्रबंधक योगेश शास्त्री ने कहा कि यह सफलता परिचालन उत्कृष्टता, अनुशासित कार्यप्रणाली, बेहतर समन्वय और टीम भावना का परिणाम है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रबंधन, अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिक यूनियन और सभी सहयोगी विभागों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। योगेश शास्त्री ने विश्वास जताया कि बार एवं रॉड मिल भविष्य में भी उत्पादन, गुणवत्ता और उत्पादकता के नए मानदंड स्थापित करती रहेगी। इस अवसर पर बीआरएम के महाप्रबंधक आशीष, शाश्वत मोहंती, समीर पांडे और शिखर तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने भी टीम को बधाई देते हुए कहा कि टीम बीआरएम इसी उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ आगे भी नए कीर्तिमान बनाएगी।

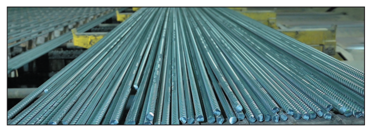

विधायक सेन की पहल : भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 8 कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से 8 विशेष कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग एवं सुरक्षा प्रदान करना है।

विधायक रिकेश सेन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता समाज और राष्ट्रहित में निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं की शुरुआत की गई है।

योजनाओं का विवरण

कमल परिवार सुरक्षा योजना-भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों को 5 लाख तक कैशलेस उपचार एवं 10 लाख का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।

कमल विद्या निधि योजना-कार्यकर्ताओं के मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 10वीं में 90% या अधिक अंक पर ?5,000, 12वीं में 90% या अधिक अंक पर 10,000 रूपये। NEET, JEE एवं अन्य

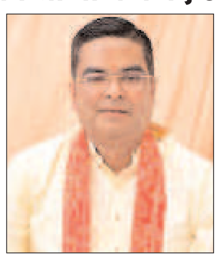

प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश पर 25,000 रूपये।

कमल रोजगार सहायता योजना-रोजगार एवं स्व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 50,000 तक ब्याजमुक्त ऋण तथा निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

कमल गृह आवास सहायता योजना-घर की मरम्मत, शौचालय निर्माण एवं सोलर सुविधा के लिए 25,000 तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

कमल पेंशन योजना-65 वर्ष से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर भाजपा कार्यकर्ताओं को 2,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

कमल धार्मिक तीर्थ यात्रा योजना-भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्ष में एक बार परिवार सहित छत्तीसगढ़ के किसी भी तीर्थस्थल की यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

कमल स्वास्थ्य योजना-कार्यकर्ताओं एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों को सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड एवं एंडोस्कोपी जैसी जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।

कमल आर्थिक सहायता योजना-भाजपा कार्यकर्ता के परिवार में मृत्यु होने पर दशगात्र संस्कार हेतु 20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

विधायक रिकेश सेन ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को केवल सम्मान देना ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक संबल उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल कार्यकर्ताओं के मनोबल को और अधिक मजबूत करेगी तथा संगठन और समाज सेवा के प्रति उनका समर्पण और बढ़ेगा।

AIDYO का अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस : दुर्ग में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, "खाली पद भरो, NTA भंग करो" के नारे के साथ युवाओं का प्रदर्शन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने बेरोजगारी, पेपर लीक और परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ मंगलवार को अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस मनाया। संगठन की छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग में जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्र सरकार से 4 प्रमुख मांगें की गईं। प्रदर्शन में आत्माराम साहू, पूजा सागर, तिरित साहू, पूनम यादव, सती कुमारी, शिवानी यादव सहित बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।

"2 करोड़ नौकरी का वादा सिर्फ जुमला" : AIDYO के राज्य सचिव आत्माराम साहू ने कहा कि देश में बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केंद्र के 78 मंत्रालयों और विभागों में 9.78 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा जुमला साबित हुआ है। पेपर लीक और भ्रष्टाचार ने युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है।

छत्तीसगढ़ के हालात पर उन्होंने कहा कि विधानसभा में सरकार के लिखित उत्तर के अनुसार राज्य में 16,24,105 पंजीकृत बेरोजगार युवा हैं। जनवरी 2024 से जून 2025 तक 18 महीनों में इनमें से एक को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। हर महीने बेरोजगारों की सूची में 17,000 नए नाम जुड़ रहे हैं। राज्य का 74% कार्यबल अनौपचारिक नौकरियों में है, जिन्हें न अनुबंध है न सामाजिक सुरक्षा।

आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक : साहू ने NCRB 2024 का हवाला देते हुए कहा कि देश में रोज औसतन 40-41 बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी 2021 में 2,040 दैनिक वेतनभोगियों ने रोजगार संकट के कारण आत्महत्या की थी। आर्थिक तंगी से युवाओं में अवसाद, नशा और अपराध बढ़ रहा है।

ये रहीं 5 मुख्य मांगें : सभी रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती और नए रोजगार का सृजन किया जाए, NTA को तुरंत भंग किया जाए, परीक्षा में पूरी पारदशिर्ता हो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, प्रश्नपत्र से लेकर परीक्षा तक की जिम्मेदारी सरकारी एजेंसी के पास हो और नॉमर्लाइजेशन प्रक्रिया समाप्त की जाए।

AIDYO ने 4 से 8 जुलाई तक पूरे देश में विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है। संगठन ने युवाओं से अपील की कि वे संगठित होकर छात्र-युवा आंदोलन को तेज करें ताकि समाज की युवा शक्ति को बर्बाद होने से बचाया जा सके।

बीएसपी में सफल संयुक्त आपदा प्रबंधन ने किया मॉक ड्रिल

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के कोक ओवन एवं कोल केमिकल्स विभाग के सीसीडी-3, यूनिट-500 में मंगलवार को संयुक्त आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। अभ्यास में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, अग्निशमन सेवाएं और बीएसपी के विभिन्न विभागों ने भाग लिया। ड्रिल का उद्देश्य कोक ओवन गैस रिसाव जैसी आपातकालीन परिस्थिति में विभिन्न एजेंसियों की तत्परता, समन्वय और बचाव क्षमता का परीक्षण करना था।

कैसा था परिदृश्य : यूनिट-500 के स्क्रबर क्षेत्र में अमोनिया स्क्रबर गैस बायपास वाल्व से कोक ओवन गैस रिसाव की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। हाइड्रोजन सल्फाइड स्क्रबर आउटलेट गैस लाइन की मरम्मत के दौरान बायपास वाल्व पूर्णतः आइसोलेट नहीं होने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल गई। इस दौरान कार्यरत 8 श्रमिकों में से 7 गैस के संपर्क में आकर अचेत हो गए।

तत्काल बचाव अभियान : स्थिति की गंभीरता देखते हुए उप महाप्रबंधक (सीसीडी) जीपी पटेल ने आपातकाल की घोषणा कर क्षेत्र खाली कराया। महाप्रबंधक (सीसीडी) एवं इंसिडेंट कंट्रोलर आनंद शुक्ला ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव का नेतृत्व किया। मुख्य महाप्रबंधक (कोक ओवन एवं कोल केमिकल्स) एवं चीफ इंसिडेंट कंट्रोलर

तुलाराम बेहरा ने पूरे अभियान की निगरानी कर सभी एजेंसियों में समन्वय सुनिश्चित किया।

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीएसपी अग्निशमन दल ने एससीबीए किट पहनकर क्षेत्र में प्रवेश कर सभी अचेत श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार केंद्र पहुंचाया। प्लांट कंट्रोल, मुख्य चिकित्सा पोस्ट, गैस सुरक्षा विभाग, सीआईएसएफ, पर्यावरण प्रबंधन, सिविल डिफेंस और एचआरडी ने भी आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार कार्य किया। गैस स्तर सामान्य पाए जाने के बाद क्षेत्र को सुरक्षित घोषित कर सामान्य परिचालन शुरू किया गया।

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद : मॉक ड्रिल का अवलोकन कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन) ए.के. चक्रवर्ती, डीआईजी (सीआईएसएफ) एनएन त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक (पीपीसी) पी.आर. भल्ला, मुख्य महाप्रबंधक (कोक ओवन एवं कोल केमिकल्स) तुलाराम बेहरा, मुख्य महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं) देबदत्त सतपथी सहित एनडीआरएफ के निरीक्षक एनके प्रधान और एसडीआरएफ के टीम लीडर ईश्वर खरे ने किया। सभी ने संयुक्त बचाव अभियान की सराहना कर सुझाव दिए।

पोस्ट ड्रिल समीक्षा बैठक

बाद में एचआरडी में कार्यपालक निदेशक (संकार्य) राकेश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। राकेश कुमार ने सभी एजेंसियों के समन्वय और प्रतिबद्धता की सराहना की। आभार मुख्य महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं)

मैंने कभी खुद को शर्मिला टैगोर का दामाद समझकर इंडस्ट्री में काम नहीं किया

अभिनेता और फिल्ममेकर कुणाल खेमू इन दिनों अपने नए रियलिटी शो 'अलायंस' को लेकर चर्चा में हैं। कुणाल ने हाल ही में उस सवाल का जवाब दिया, जो अक्सर उनसे पूछा जाता है। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक का हिस्सा बनने के बाद क्या उन्हें कभी किसी तरह का दबाव या उम्मीदों का बोझ महसूस हुआ? इस पर कुणाल ने कहा कि उन्होंने कभी भी निजी रिश्तों को अपने काम और कला के बीच नहीं आने दिया। आईएएनएस से खास बातचीत में सवाल का जवाब देते हुए कुणाल ने कहा, ''नहीं, मेरे लिए मेरी कला और मेरे भीतर का कलाकार सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही मेरे लिए सबसे अहम है। सच कहूं तो मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं कि मैं शर्मिला टैगोर का दामाद हूं।'' अगर मैं यह कहूं कि मैं इस बारे में सोचता हूं या इससे बचने की कोशिश करता हूं, तो यह झूठ होगा। यह बात मेरे दिमाग में रहती ही नहीं है।'' अभिनेता ने आगे कहा, ''मेरी क्रिएटिव जर्नी हमेशा एक्टिंग और फिल्ममेकिंग के प्रति मेरे पैशन से प्रेरित रही है। मैंने कभी इस बात को महत्व नहीं दिया कि मैं किस परिवार का हिस्सा हूं। किसी कलाकार की असली पहचान उसके काम से बनती है, न कि उसके पारिवारिक रिश्तों से।'' बता दें कि कुणाल खेमू ने अभिनेत्री सोहा अली खान से 25 जनवरी 2015 को शादी की थी। सोहा अली खान, दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और दिवंगत क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी की बेटी हैं। कुणाल और सोहा की पहली मुलाकात साल 2009 में फिल्म 'ढूंढते रह जाओगे' के सेट पर हुई थी। वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। शादी के दो साल बाद, सितंबर 2017 में दोनों ने अपनी बेटी इनाया नौमी खेमू का स्वागत किया। दोनों अक्सर अपनी बेटी के साथ बिताए खास पलों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं, जिन्हें फैंस भी काफी पसंद करते हैं।

'अल्फा' से 'बेबी डू डाई डू' की भिड़ंत पर बोलीं हुमा कुरैशी

बीते दिन शुक्रवार को यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' रिलीज हुई, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी अहम भूमिकाओं में हैं। इसी के साथ हुमा कुरैशी अभिनीत 'बेबी डू डाई डू' ने भी दस्तक दी। दोनों फिल्मों के क्लैश पर हाल ही में हुमा कुरैशी ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने 'अल्फा' का स्वागत करते हुए एक्शन फिल्मों में अपनी दिलचस्पी का भी जिक्र किया।

'बेबी डू डाई डू' में हुमा की भूमिका क्या है?

फिल्म 'बेबी डू डाई डू' में हुमा कुरैशी ने एक मूक बधिर दिव्यांग का किरदार अदा किया है। इस भूमिका के लिए उनकी काफी तारीफ हो रही है। हाल ही में हुमा ने फिल्म पर बात की। हुमा ने कहा, 'मैं एक ऐसी महिला किलर का रोल कर रही हूं, जो सुन या बोल नहीं सकती। यह कोई कमी या कमजोरी नहीं है, बल्कि असल में उसकी ताकत है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किलर हमेशा पुरुष ही होता है। लेकिन कोई महिला क्यों नहीं हो सकती?

महिला प्रधान एक्शन फिल्मों के लिए उम्मीद भरा दौर

महिला प्रधान एक्शन फिल्मों के लिए बढ़ते स्पेस के बारे में बात करते हुए हुमा कुरैशी ने कहा कि दर्शकों की बदलती उम्मीदों और अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की वजह से, मौजूदा समय महिलाओं के नेतृत्व वाली एक्शन फिल्मों के लिए एक उम्मीद भरा दौर है। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे रहने वाले हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। बातचीत के दौरान हुमा कुरैशी ने 'बेबी डू डाई डू' और 'अल्फा' के बॉक्स ऑफिस टकराव पर भी चुप्पी तोड़ी।

मैं प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देख रही

हुमा ने दोनों महिला प्रधान फिल्मों के एक साथ आने का स्वागत किया। हुमा ने कहा, 'मैं 'अल्फा' को कॉम्पिटिशन के तौर पर नहीं देखती। मुझे लगता है कि हर तरह की फिल्में बनने और देखे जाने की गुंजाइश है। हमारी फिल्म इंडिपेंडेंटली बनी है। मैं यह भी नहीं देख रही कि उस वीकएंड और क्या रिलीज हो रहा है? बस अपने दर्शकों तक पहुंचना चाहती हूं। दूसरी ओर, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसे दौर में हैं जहां बॉक्स ऑफिस पर दो महिला-प्रधान फिल्में टकरा रही हैं। हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां यह असलियत है। हम सभी को, महिला-प्रधान कंटेंट को और ज्यादा बढ़ावा मिले। मैं अपने साथ-साथ अपनी सहेलियों के लिए भी चीयर करती रहूंगी'।

रणवीर सिंह की 'प्रलय' को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट

'धुरंधर' की सफलता के बाद फैंस रणवीर सिंह की अगली बड़ी फिल्म 'प्रलय' के बारे में अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्ममेकर जय मेहता की जॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि फिल्म की शूटिंग इस साल के आखिर में शुरू हो सकती है। साथ ही फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में शूट किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'प्रलय' की शूटिंग सितंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर ने इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। एक सोर्स ने पिंकविला को बताया, 'रणवीर 2026 के दूसरे हाफ में जय मेहता के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में होगी और उन्होंने तैयारी शुरू भी कर दी है। फिल्म के बड़े पैमाने और जॉनर को देखते हुए इसके लिए जबरदस्त फिजिकल और इमोशनल तैयारी की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का प्री-प्रोडक्शन अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, जहां जय मेहता और उनकी टीम उन टेक्नीशियन्स के साथ मिलकर काम कर रही है जो पहले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेकर्स प्रोडक्शन शुरू होने से पहले फिल्म की विशाल पोस्ट-एपोकैलिप्टिक दुनिया बनाने पर ध्यान दे रहे हैं।

फिल्म में वीएफएक्स का होगा जबरदस्त इस्तेमाल

रिपोर्ट के अनुसार, 'प्रलय' काफी हद तक विजुअल इफेक्ट्स पर निर्भर करेगी और राइटिंग टीम स्क्रीनप्ले और फिल्म की बड़ी जॉम्बी दुनिया को बेहतर बनाने का काम जारी रखेगी। कहा जा रहा है कि रणवीर भी डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान क्रिएटिव चर्चाओं में एक्टिव रूप से शामिल हैं।

दीया मिर्जा के समर्थन में उतरीं ऋचा; ट्रोल्स को दिया जवाब

एक्टर दीया मिर्जा को ऑनलाइन ट्रोल किया गया, जब उन्होंने एक घटना के बारे में बताया कि कैसे उनके 5 साल के बेटे अव्यान ने प्लास्टिक बैग में नारियल पानी लाने पर एक डिलीवरी एजेंट को डांटा। सोहा अली खान के पॉडकास्ट का क्लिप वायरल होने के बाद इंटरनेट पर कई लोगों ने दीया और उनके बेटे की आलोचना की और उन पर अहंकार दिखाने का आरोप लगाया। अब इस आलोचना के बीच एक्टर ऋचा चड्ढा दीया के समर्थन में सामने आई हैं। ऋचा ने एक्स पर एक यूजर द्वारा शेयर किए गए नोट को रीपोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि दीया पर्यावरण के प्रति जागरूकता का उपदेश देती है और फिर अपनी जगुआर कार में घूमती हैं। ऋचा ने जवाब में एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, 'आप लोग सोचते हैं कि एक्टर्स क्यों नहीं बोलते? कुछ करो तो बुरा, कुछ मत करो तो बुरा!

हमेशा की तरह बेवकूफ लोगों की बेइज्जती के अलावा, ये भी है! अरे यार, अभिनेताओं की मानसिक सेहत का क्या है? आए दिन आत्महत्या करके सनसनीखेज खबरों को हवा देना भी तो कलाकारों का कर्तव्य होना चाहिए ना? है ना? विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं को सिलेबस से बाहर कुछ भी कहने पर शर्मिंदा किया जाएगा। उन्होंने क्लाइमेट पर एक प्यारी सी शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। इन चीजों को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप 5 साल के बच्चे को परेशान कर सकते हैं, तो बेसिक गूगल सर्च भी तो कर ही सकते हैं, है ना?'

क्या 'हेरा फेरी 3' का निर्देशन करेंगे प्रियदर्शन

प्रियदर्शन ने हाल ही में फिल्म 'भूत बंगला' का निर्देशन किया है। इन दिनों वह 'हैवान' पर काम कर रहे हैं। इस बीच निर्माता फिरोज ए नाडियाडवाला ने बताया है कि 'हेरा फेरी' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्टर नहीं करेंगे। उन्होंने अक्षय कुमार और परेश रावल जैसे एक्टर्स के साथ अपने रिश्तों के बारे में भी बात की।

कैसे हैं अक्षय कुमार के साथ रिश्ते?

'वैरायटी इंडिया' से बातचीत में फिरोज ने अक्षय कुमार के साथ अपने रिश्ते के बारे में कहा 'हमारा रिश्ता भाईचारे जैसा है। यह पैसे और दबाव से कहीं ऊपर है। हमारा रिश्ता 1996-97 से है। यह साथ रहने और साथ काम करने पर आधारित है और यही हमारा रिश्ता है।'

नाडियाडवाला ने की परेश रावल की तारीफ

परेश रावल की तारीफ करते हुए फिरोज ए नाडियाडवाला ने कहा 'डिक्शनरी में परेश भाई के बारे में बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। वह कमाल के हैं। उनके विचार, सपोर्ट और कोशिशें आम लोगों से कहीं बढ़कर हैं। उनके काम करने के तरीके में कुछ आध्यात्मिक बात है।'

प्रियदर्शन नहीं होंगे फिल्म का हिस्सा

जब 'हेरा फेरी 3' की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा गया, तो फिरोज ने संक्षेप में लेकिन भरोसा दिलाते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'सब कुछ सही रास्ते पर है और सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।' जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रियदर्शन इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए वापस आएंगे, तो फिरोज ने सीधा और साफ जवाब दिया, जिससे अटकलों की कोई गुंजाइश नहीं बची। उन्होंने कहा, 'नहीं, प्रियदर्शन इसका हिस्सा नहीं हैं।'

आज जब मैं 40 साल की हो गई हूं, मेरी सोच अलग हो चुकी है

पिछले दिनों अपनी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नर्स की भूमिका में तारीफें बटोरने वाली कंगना इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं रिएलिटी शो 'लॉकअप' को लेकर। उनकी 'क्वीन 2' को लेकर भी खबरें हैं है कि वो फिल्म पूरी हो चुकी है। अपनी भूमिकाओं में जान डाल देने वाली यह अभिनेत्री पॉलिटिशियन के रूप में भी धाकड़ हैं। हिमाचल की रहने वाली कंगना जब छोटी उम्र में घर वालों की खिलाफत करके दिल्ली आई, तब तक उनके लिए अभिनेत्री बनने का रास्ता बहुत मुश्किल रहा। मगर पहले गैंगस्टर, फिर तनु वेड्स मनु और क्वीन ने उन्हें अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। कई खट्टे-मीठे अनुभवों से गुजरी कंगना अपने जीवन की उपलब्धियों में कई लोगों के योगदान की बात करती हैं।

40 की उम्र में सोच अलग हो गई है

कंगना का मानना है कि अपने अकेले दम पर कोई भी इंसान कुछ हासिल नहीं कर सकता। वे कहती हैं, 'इंसान की जिंदगी में कई लोग होते हैं, जो किस्मत को संवारते हैं। माता, पिता, गुरु से शुरू होने वाला ये सिलसिला चलता जाता है। आज जो शब्दावली मैं बोल भी पा रही हूं, तो उसमें कई लोगों का योगदान है। जब मैं अभिनय के क्षेत्र में आई, उस वक्त अनुराग बसु मेरे करियर में अहम साबित हुए, जिन्होंने मुझे गैंगस्टर जैसी फिल्म दी और फिर विकास बहल जैसे फिल्मकार जिन्होंने क्वीन से मुझे सफलता दिलाई। आज जब मैं 40 साल की हो गई हूं, तो मेरी सोच अलग हो चुकी हैं। ये सोच वक्त के साथ आती है। आप जब अस्पताल में किसी सर्जरी में जा रहे होंगे, तब आपको लगेगा कि ये नर्स और डॉक्टर ही आपके लिए सब कुछ हैं।'

आज हर वो शख्स क्रिएटर है, जिसके पास फोन है

पिछले कुछ समय से इंडस्ट्री पर स्लो डाउन के बादल मंडरा रहे हैं और कहा जा रहा है कि फिल्मों का बजट, स्टार्स की फीस जैसे फैक्टर्स में यदि सुधार नहीं हुआ, तो फिल्म उद्द्योग खतरे में पड़ जाएगा। इस पर कंगना कहती हैं, 'फिल्म इंडस्ट्री को उठना तो पड़ेगा ही। मुझे याद है, आज से दस साल पहले मैं और शेखर कपूर (फिल्मकार) किसी बात पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा, कंगना जिसके हाथ में कैमरा या मोबाइल होगा, वो एक फिल्म बनाएगा। उस वक्त मुझे लगा था कि हर कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता। मुझे उनकी बात जंची नहीं थी। मगर आज देखिए, आज इंटरनेट पर लोग दो-दो मिनट की फिल्म बना रहे हैं। कोई ट्रेन में चढ़ा हुआ है, तो कोई दूर -दराज के गांव में बैठी कोई महिला दूध दुहना सिखा रही है, कोई खाना पकाना सिखा रहा है, तो कोई मेकआप टिप्स दे रहा है और आप सभी इस सिस्टम में पूरी तरह से एंगेज हो गए हैं। दूसरों की क्या कहूं, मेरे खुद के माता-पिता आज रील्स में इतना बिजी हैं। आज रिलेटेबल रोल्स खत्म होते जा रहे हैं। पुष्पा जैसा मजदूर आपने कब देखा था? शायद अमिताभ बच्चन जी के दौर में।'

जॉन सर सही मायनों में कूल हैं

कंगना की नई फिल्म को लेकर एक दिलचस्प बात ये है कि इसका शीर्षक जॉन अब्राहम के पास रजिस्टर था, मगर उन्होंने खुशी-खुशी इसे कंगना को दे दिया। इस पर कंगना कहती हैं, 'इंसान वहीं मांगता है, जहां उसे उम्मीद होती है। जॉन सर के साथ शूटआउट एट वडाला की थी। उनके बारे में जो कहा जाता है कि वे अपने काम से काम रखते हैं और सही मायनों में कूल गाय है। उनके साथ एक कमाल का कंफर्ट था। मैं इसे दोस्ती तो नहीं कहूंगी, क्योंकि दोस्ती की अलग-अलग परिभाषा होती है। जो मैंने उनका बर्ताव देखा, तो पाया कि वे अपने काम से काम रखते हैं, मगर ऐसा भी नहीं हैं कि दुनिया-जहान से ला-ताल्लुक हैं। अप्रोचेबल हैं, रीचेबल हैं,, अगर हैं अपनी दुनिया में। मैंने जब भी उनके साथ काम, किया, मुझे बहुत मजा आया। हमारी इस फिल्म का नाम पहले नर्सेज ऑफ कामा था, मगर शीर्षक में वो बात नहीं आ पा रही थी। तब टाइटल आया, भारत भाग्य विधाता, मगर फिर पता चला कि ये शीर्षक तो जॉन सर के पास है। जाहिर है, वो निर्माता भी हैं, तो एक निर्माता कई सालों तक पैसे जमा कर करके अपने टाइटल को सुरक्षित रखता है। मुझे लगा मैं इस शीर्षक के लिए किसी तरह से उन्हें मना ही लूंगी, मगर उसकी नौबत नहीं आई। मेरे कहने भर से उन्होंने मुझे दे दिया। उनका दिल बहुत बड़ा है।'

बेमेतरा जिला में भारी बारिश को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क, सभी विभाग है अलर्ट

अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर ले रहे हैं स्थिति का जायजा

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

जिले में लगातार हो रही वर्षा एवं मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की संभावना को देखते हुए कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देश पर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में कार्य कर रहा है। संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। जिले के सभी अनुविभागों, विकासखंडों, नगरीय निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों एवं मैदानी अमले को सतर्क रहने तथा लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आम नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सवोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सभी विकासखंडों में आवश्यक संसाधनों, राहत एवं बचाव दलों तथा आपातकालीन व्यवस्थाओं को तैयार रखा गया है। किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है।

जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों, पुल-पुलियों, नालों, नदी-नालों तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर

तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

इसी क्रम में साजा अनुविभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम रोद्रा स्थित डोटूनाला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां की स्थिति सामान्य पाई गई। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा जलस्तर एवं आवागमन की स्थिति पर सतत नजर बनाए रखी गई है। जिला प्रशासन ने बताया कि वतर्मान में जिले की स्थिति पूरी तरह सामान्य एवं नियंत्रण में है। कहीं से भी किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसके बावजूद प्रशासन किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं।

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि भारी बारिश एवं मेघ गजर्ना के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। नदी, नाले, पुल-पुलियों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों को पार करने का प्रयास न करें तथा बच्चों को ऐसे स्थानों से दूर रखें। खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, ऊंचे पेड़ों तथा बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचें। किसी भी आपात स्थिति अथवा असामान्य परिस्थिति की जानकारी तत्काल स्थानीय प्रशासन अथवा संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि आमजन के सहयोग, सतकर्ता एवं जागरूकता से किसी भी संभावित आपदा का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है। जिला प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ चौबीसों घंटे कार्यरत है तथा प्रत्येक परिस्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

खास खबर

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े महिलाओं के कदम विचारपुर में सिलाई प्रशिक्षण शिविर संपन्न

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत विचारपुर में आयोजित सिलाई मशीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हो गया। राशि वेलफेयर सोसाइटी राजनांदगांव द्वारा आयोजित इस शिविर में गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ बड़े उत्साह और लगन से सिलाई के गुर सीखे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित अतिथियों द्वारा सभी सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

समारोह को संबोधित करते हुए राशि वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष सुश्री संतोषी साहू एवं सचिव तरुण साहू ने प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा यह प्रशिक्षण महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने और समाज में एक नई पहचान बनाने में मददगार साबित होगा। आज के दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। गांव में ही रहकर इस हुनर के माध्यम से वे खुद का रोजगार शुरू कर सकती हैं और अपने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान कर सकती हैं।

प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जब महिलाओं के हाथों में प्रमाण-पत्र सौंपे गए, तो उनके चेहरों पर आत्मनिर्भरता की चमक साफ देखी जा सकती थी। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं ने राशि वेलफेयर सोसाइटी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस शिविर ने उन्हें न सिर्फ एक नया हुनर सिखाया है, बल्कि जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा भी दी है। अब वे स्वयं का सिलाई कार्य शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। इस गरिमामय समापन समारोह के अवसर पर ग्राम पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधि, राशि वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य, ट्रेनर, गणमान्य ग्रामीणजन सहित बड़ी संख्या में महिलाएं व ग्रामीण उपस्थित रहे।

उप निरीक्षक संवर्ग, सूबेदार और प्लाटून कमांडर (प्रारंभिक) परीक्षा 12 जुलाई को

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का आयोजन 12 जुलाई 2026 (रविवार) को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। राजनांदगांव जिले में परीक्षा के लिए 7 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।

कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशन में परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। परीक्षा संचालन से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है तथा परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। गोपनीय परीक्षा सामग्री के सुरक्षित संधारण, वितरण एवं परीक्षा उपरांत नियमानुसार संकलन एवं प्रेषण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से पर्याप्त पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र पहुंचना सुनिश्चित करें। आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ प्रवेश पत्र, वैध फोटो पहचान पत्र तथा आयोग द्वारा अनुमत सामग्री ही लेकर आएं। परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूणर्तः प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए केन्द्राध्यक्षों, पयर्वेक्षकों एवं नियुक्त अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समय पर परीक्षा केन्द्र पहुंचने तथा परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाएं रखने की अपील की है।

जल जीवन मिशन के कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा से कोई समझौता नहीं-कलेक्टर

हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

कलेक्टर एवं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्ष प्रतिष्ठा ममगाई की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित एवं प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं की प्रगति, समूह जलप्रदाय योजनाओं, फंड रिलीज, Comprehensive Implementation and Reform Plan (CIRP), हर घर जल अभियान तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। योजना के प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता, पारदशिर्ता एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनावश्यक विलंब अथवा गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रस्तावित एवं प्रगतिरत समूह जलप्रदाय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। योजनाओं की वतर्मान प्रगति, शेष कार्यों एवं समयबद्ध पूणर्ता को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली गई। साथ ही समूह जलप्रदाय योजनाओं के फंड रिलीज के अनुमोदन संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए आवश्यक स्वीकृतियों एवं वित्तीय प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

समीक्षा के दौरान समय-सीमा में पूर्ण नहीं हो पा रही समूह जलप्रदाय योजनाओं की समयावधि से संबंधित प्रस्तावों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। कलेक्टर ने प्रत्येक प्रकरण की योजनावार समीक्षा करते हुए विलंब के कारणों की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि जहां तकनीकी अथवा प्रशासनिक कारणों से कार्य प्रभावित हुए हैं, वहां समस्याओं का त्वरित निराकरण कर कार्यों में अपेक्षित गति लाई जाए।

बैठक में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा प्रदत्त Comprehensive Implementation and Reform Plan (CIRP) के क्रियान्वयन एवं अनुमोदन से जुड़े विषयों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीआईआरपी के अंतर्गत निर्धारित सभी गतिविधियों एवं सुधारात्मक उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की योजनावार समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, पाइपलाइन विस्तार, जल स्रोतों की उपलब्धता, जल गुणवत्ता परीक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हर घर जल अभियान के तहत प्रत्येक पात्र परिवार तक कायर्शील घरेलू नल कनेक्शन एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना सभी संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कार्यदायी एजेंसियों एवं ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन एजेंसियों अथवा ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण करने, कार्यों की गुणवत्ता की सतत जांच करने तथा प्रत्येक परियोजना की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिन योजनाओं में किसी प्रकार की तकनीकी, प्रशासनिक अथवा अन्य बाधाएं हैं, उनका शीघ्र निराकरण कर कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि जिले के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को समय पर सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। बैठक के अंत में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई तथा जल जीवन मिशन से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती प्रेमलता पदमाकर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से कायर्पालन अभियंता जेपी गोंड कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग सीएस शिवहरे, सीएसपीडीसीएल के जेएस भटनागर, कृषि उपसंचालक एम.डी. डडसेना, सहायक सांख्यिकी अधिकारी राजकुमार वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

आईजी बालाजी राव ने की रेंज की समीक्षा, बेहतर पुलिसिंग के निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद पहली बार मोहला-मानपुर जिले में राजनांदगांव पुलिस रेंज की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) बालाजी राव ने की। इसमें राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कबीरधाम और मोहला-मानपुर के पुलिस अधीक्षकों सहित रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए।

स्थानीय पुलिस को-ऑडिर्नेशन सेंटर में आयोजित बैठक में बेहतर पुलिसिंग, तकनीक आधारित जनोन्मुखी पुलिस व्यवस्था, लंबित अपराधों के त्वरित निराकरण, कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा पुलिस कार्यप्रणाली में नवाचारों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई। विशेष रूप से पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करने और जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।

बैठक के दौरान चारों जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने जिलों में संचालित नवाचारों का प्रस्तुतीकरण किया। आईजी बालाजी राव ने सफल नवाचारों को आवश्यकता अनुसार पूरे रेंज में लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित अपराध, शिकायतों, सीएम हेल्पलाइन 1076, CCTNS प्रशिक्षण, रेडियो कम्युनिकेशन और अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस अवसर पर मोहला-मानपुर जिले की डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल बुक का विमोचन भी किया गया। बैठक के बाद कलेक्टर तूलिका प्रजापति की उपस्थिति में आईजी बालाजी राव और अन्य अधिकारियों ने रक्षित केंद्र परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

बैठक में राजनांदगांव की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई की पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा, कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, मोहला-मानपुर के पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह सहित रेंज के अन्य राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे।

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन व समयबद्ध निराकरण पर दें विशेष ध्यान : कलेक्टर प्रजापति

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर जी.आर. मरकाम, अपर कलेक्टर मिथलेश डोंडे, एसडीएम मोहला हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर अमित नाथ योगी सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर प्रजापति ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी विभागों को निर्देशित किया कि आवेदनों का प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को पोर्टल का नियमित अवलोकन करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बस्तर मुन्ने सर्वेक्षण एवं डेटा एंट्री कार्य प्रगति की समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जननी सुरक्षा योजना में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित

अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने किसान सम्मान निधि के भुगतान की स्थिति की जानकारी ली तथा शेष पात्र किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वतर्मान कृषि कार्यों को देखते हुए उन्होंने जिले में खाद एवं बीज की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों से खाद भंडारण की स्थिति की जानकारी ली। कलेक्टर ने राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुए उनके निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं जनसामान्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों को योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाने तथा हितग्राही-आधारित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्कूलों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आगामी शिक्षण सत्र में बेहतर परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए काययोजना बनाकर प्रभावी ढंग से कार्य करें। इस दौरान नवोदय विद्यालय के संचालन से संबंधित विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने वनाधिकार पत्रों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जनपद पंचायत के सीईओ से स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मौके पर उन्होंने भू-अर्जन प्रकरणों की वतर्मान स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को उनकी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में लाएं तेजी : कलेक्टर जितेन्द्र यादव

जलभराव वाले क्षेत्रों में प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश,

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों एवं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए सभी नगरीय निकायों में जलभराव वाले स्थानों का चिन्हांकन कर प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन 1076, मुख्यमंत्री जनदर्शन, जन शिकायतों, सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, साप्ताहिक समय-सीमा, पीजीएन, पीजी पोर्टल एवं जनदर्शन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा सत्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने तथा सभी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार

सत्यापन का कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का परीक्षण शीघ्र पूर्ण कर पात्र हितग्राहियों के घरों में सोलर पैनल स्थापना का कार्य तेजी से कराया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने प्राकृतिक सौर ऊर्जा के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए वार्डों एवं ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से सूर्यघर सभाएं आयोजित करने तथा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के बिजली व्यय में कमी लाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। जिले में अब तक 3 हजार 828 हितग्राहियों के यहां सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे वे स्वयं ऊर्जा उत्पादक बन चुके हैं और उन्हें अतिरिक्त बिजली उत्पादन से आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जिले में संचालित एचपीवी टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित इस अभियान के तहत किशोरी बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को अभिभावकों एवं बच्चों को एचपीवी वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए अत्यंत प्रभावी है। जिले में अब तक 4 हजार 281 किशोरी बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण किया जा चुका है।

कलेक्टर ने हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग का कार्य अनिवार्य रूप से तेज गति से करने के निर्देश दिए। उन्होंने हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की समय पर सोनोग्राफी, उपचार, आवश्यक दवाइयों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य की प्रतिदिन मोबाइल के माध्यम से मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर प्रेमप्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम डोंगरगढ़ एम भार्गव, एसडीएम राजनांदगांव गौतम पाटिल, एसडीएम डोंगरगांव श्रीकांत कोराम सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

पट्टा सर्वे शिविर : आज से होगा डोर-टू-डोर सत्यापन कार्य

कवर्धा। जिला प्रशासन एवं नगर पालिका परिषद कवर्धा के संयुक्त तत्वाधान में आवासहीन परिवारों को पट्टा प्रदाय किये जाने हेतु दस्तावेज पंजीकरण किये जाने हेतु वीर सावरकर भवन एवं ठाकुर पारा स्थित सामुदायिक भवन में शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में पहुंचकर 213 हितग्राहियों ने अपना पंजीयन कराया। सभी हितग्राहियों को शासन द्वारा चाही गई आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करने को कहा एवं 09 जुलाई से डोर-टू-डोर जाकर लोगों के दस्तावेज का सत्यापन कर शासन की योजना का लाभ दिलाया जायेगा। नगर पालिका क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार नियम, 2023 के तहत पात्र परिवारों को शासकीय भूमि का नि :शुल्क पट्टा 30 वर्षों के लिए प्रदान किया जाना है। आवासहीन एवं पात्र हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

धूमधाम से मनाया भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन का जन्मदिन

सांसद, पूर्व मंत्री सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दी शुभकामनाएं, मंदिर में पूजा, वृद्धजनों को भोजन और गौ सेवा से की शुरुआत

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन का जन्मदिन मंगलवार को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

राजनीतिक हस्तियों की रही मौजूदगी

जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने वालों में प्रमुख रूप से दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला भिलाई संगठन प्रभारी रामजी भारती, विधायक डोमन लाल कोसेवाड़ा, खादी ग्रामोद्योग अध्यक्ष राकेश पांडे, सिंधी साहित्य अकादमी अध्यक्षा सुषमा जेठानी, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री जागेश्वर साहू, रमशीला साहू, दुर्ग महापौर अलका बाघमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल रहे।

इसके अलावा जामुल नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर, अहिवारा नगर पालिका अध्यक्ष विद्यानंद कुशवाहा, दुर्ग जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन, धमधा जनपद अध्यक्ष लीमन साहू, भिलाई निगम नेता प्रतिपक्ष भोजराज, उपनेता दया सिंह, पूर्व महापौर निमर्ला यादव, दुर्ग भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र कौशिक, प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा सहित महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान, ओबीसी, अल्पसंख्यक मोर्चा और 13 मंडलों के अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित थे। महिला मोर्चा ने उन्हें 5 प्रकार के फलों से तौलकर सम्मानित किया।

सेवा कार्यों से की शुरुआत

जन्मदिन की शुरुआत सेक्टर-9 स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अचर्ना से हुई। इसके बाद देवांगन सेक्टर-3 स्थित फील परमार्थ फाउंडेशन पहुंचे और निराश्रित एवं वृद्धजनों को भोजन वितरित किया। तत्पश्चात कोसा नगर गोठान में गौवंश को घास एवं गुड़ खिलाकर सेवा कार्य किया। इस दौरान जिला मंत्री विनोद सिंह, पारस जघेल, मदन सेन, सचिन ताम्रकार, युवा मोर्चा अध्यक्ष सौरभ जायसवाल सहित कई पदाधिकारी साथ रहे।

दोपहर से देर शाम तक जिला भाजपा कार्यालय में शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। पूरे दिन कार्यालय में उत्सव जैसा माहौल रहा। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ चन्ना केशवलु, गोपाल कृष्ण वर्मा, चंद्रकांता मांडले, नटवर ताम्रकर, पूनम शुक्ला, डॉ. प्रदीप चौधरी, डॉ. अनुज खरे, पार्षदगण प्रियंका भोज साहू, संजय सिंह, वीणा चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।

पटेल समाज ने शाकंभरी बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र नायक पटेल का किया गया अभिनंदन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छग शासन के शाकंभरी बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष राजेंद्र नायक पटेल का दुर्ग-भिलाई के मरार पटेल समाज के पदाधिकारियों ने पटेल विद्या मंदिर, रायपुर में अभिनंदन किया। समाज के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए शाकंभरी योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों के हित में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। साथ ही इस नियुक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री और संगठन के पदाधिकारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

इस अवसर पर महासंघ अध्यक्ष बरत राम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सुनील पटेल, कायर्कारी अध्यक्ष तेजराम पटेल, कोषाध्यक्ष लिलार सिंह पटेल, उपाध्यक्ष खेलूराम पटेल, महामंत्री केशव पटेल, दुलेश पटेल, कुबेर पटेल, कमलेश पटेल, सुदेश पटेल, महासंघ सचिव पतिराम पटेल सहित दुर्ग-भिलाई के बड़ी संख्या में सामाजिक जन उपस्थित थे। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि राजेंद्र नायक पटेल की नियुक्ति से सामाजिक जनों में हर्ष का माहौल है।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100